ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

online- jwalaexpress.com

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

वर्ष - 05, अंक -40 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 04 जून से 10 जून (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

समृद्ध, संगठित और शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला : मुख्यमंत्री

चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के 55वें केंद्रीय अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, समाज की एकता और संगठन शक्ति की सराहना

छाती-झूरानवागांव सड़क, नवीन हायर सेकेंडरी भवन, नगर पंचायत और नवा रायपुर में सामाजिक भवन हेतु भूमि की घोषणा

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस गौरवशाली समाज के केंद्रीय अधिवेशन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि चन्द्रनाहू कुर्मी-क्षत्रिय समाज समृद्ध परंपराओं, सामाजिक चेतना, संगठन क्षमता और उत्कृष्ट मूल्यों का वाहक है।

यह वही समाज है जिसने देश को छत्रपति शिवाजी महाराज और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिनके आदर्श आज भी राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोई भी समाज शिक्षा, संगठन, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बल पर निरंतर आगे बढ़ता है। चन्द्रनाहू समाज ने कृषि, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, सामाजिक सेवा और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की नई पीढ़ी शिक्षा, तकनीकी दक्षता और नवाचार के माध्यम से विकास की नई इबारत लिख रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने छाती से झूरानवागांव तक सड़क निर्माण, ग्राम छाती को भविष्य में नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने, नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण तथा समाज के लिए नवा रायपुर में सामाजिक भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं का उपस्थित जनसमुदाय ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऐसे अधिवेशन केवल सामाजिक आयोजन नहीं होते, बल्कि समाज को संगठित, जागरूक और सशक्त बनाने के प्रभावी मंच होते हैं। जब समाज के लोग एकत्र होकर विचार-विमर्श करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और नई पीढ़ी के लिए दिशा निर्धारित करते हैं, तब सामाजिक एकता और विकास की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। उन्होंने समाज द्वारा प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, खेल, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों और विद्यार्थियों के सम्मान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मान की संस्कृति समाज में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। ऐसे प्रयास युवाओं को आगे बढ़ने और नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार बनती है। राज्य सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने समाज के उद्यमियों और व्यवसायियों से राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने और निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। नई औद्योगिक नीति में युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।

समझौते से पहले नहीं देंगे कोई राहत

ईरान की जब्त संपत्तियों पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

वॉशिंगटन (ए)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने से पहले उसकी जब्त हुई संपत्तियों को नहीं लौटाएंगे। एनबीसी न्यूज के मीट द प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों से किसी भी प्रकार की राहत केवल ईरान द्वारा भविष्य के समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद ही दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंधों में ढील देने पर चर्चा शुरू होने से पहले तेहरान को अपनी नीयत और प्रतिबद्धता का सबूत देना होगा। उन्होंने कहा, समझौते के बाद। हां। अगर वे ठीक व्यवहार करते हैं, अगर वे अच्छा काम करते हैं, तो हम बातचीत शुरू करेंगे। हां।

लेबनान को लेकर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ने यह भी स्पष्ट किया कि वह लेबनान को तेहरान के साथ किसी अल्पकालिक समझौते में शामिल करने पर जोर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे ऐसा देखना चाहेंगे, लेकिन मैं इसकी मांग नहीं कर रहा हूं। पश्चिम एशिया में कई महीनों से जारी संघर्ष और बढ़े तनाव के बाद स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ट्रंप प्रशासन भी संभावित शांति समझौते के लिए कोशिश में जुटा हुआ है।

फिर दी ईरान पर हमले की धमकी

ट्रंप ने मांग की कि भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ताकार परमाणु हथियार विकास से संबंधित प्रतिबंधों पर काफी हद तक सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने खास शब्दों के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो वॉशिंगटन ईरान के साथ मिलकर संवर्धित यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने का काम करेगा। ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि समझौते में यह सुनिश्चित किया जाए कि ईरान परमाणु हथियार या संबंधित क्षमताएं विकसित या खरीद न सके। ट्रंप ने कहा कि ईरानी वार्ताकारों ने शुरू में प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन बाद में अपना रुख नरम कर लिया। ट्रंप ने संकेत दिया कि कूटनीति विफल होने की स्थिति में अमेरिकी सेना बल प्रयोग के लिए तैयार है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से कहा, हम किसी समझौते के बहुत करीब हैं, अगर नहीं तो मैं उन पर जबरदस्त कार्रवाई करूंगा।

क्या अमेरिका को पता चल गया मोजतबा खामेनेई का ठिकाना?

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई से बात करने के लिए तैयार हैं। मोजतबा खामेनेई पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत में अमेरिकी हमलों में घायल होने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मुझे पता है कि वह कहां हैं या नहीं, लेकिन इसकी अच्छी संभावना है कि मुझे पता हो कि वे कहां हैं।

समाचार सार

अल्फाग्रेप की म्युचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री

नईदिल्ली। अल्फाग्रेप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अगले महीने अपनी पहली म्युचुअल फंड योजना लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अगले तीन से पांच साल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से म्युचुअल फंड कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिली है।

भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का भारी पलायन

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का मोहभंग होता दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आ रहे नए मौकों और डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार आ रही कमजोरी की वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार से ताबड़तोड़ पैसे निकाल रहे हैं। जून के पहले हफ्ते में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 43,000 करोड़ रुपये ,927 निकाल लिए हैं।

एफपीआई बेच रहे हैं शेयर, खरीद रहे हैं बॉन्ड

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की खरीदारी और बिकवाली हमेशा सुर्खियों में रहती है। जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं तो बाजार में गिरावट और अर्थव्यवस्था पर उसके असर को लेकर खूब चर्चा होती है। इस साल भी एफपीआई भारतीय इक्विटी बाजार से बड़ी रकम निकाल चुके हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है।

शेयर बाजार की सुस्ती से टॉप 7 कंपनियों को डूबे

नईदिल्ली। शेयर बाजार में पिछले हफ्ते रही सुस्ती का बड़ा असर देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर पड़ा है। टॉप-10 में से सात सबसे मूल्यवान कंपनियों के मार्केट कैप में 1.25 लाख करोड़ रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में सबसे बड़ा झटका दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा है। पिछले हफ्ते के कारोबार के दौरान बीएसई का सेंसेक्स 532.4 अंक यानी 0.71 फीसदी टूट गया।

गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दांव

जल्द हाईटेक होंगी सरहदें, परवान चढ़ेगा कारोबार, चुटकियों में मिलेगी मंजूरी

नई दिल्ली (ए)। भारत सरकार ने सीमाओं पर व्यापार और आवाजाही को पूरी तरह हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) लॉन्च करेंगे। यह एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे देश के सभी लैंड पोर्ट्स के कामकाज को एक एकीकृत प्रणाली से जोड़ने के लिए बनाया गया है।

इसके साथ ही, गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के डाउकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट्स पर नवनिर्मित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।

सुगम समन्वय और कम समय-यह नया सिस्टम सीमाओं पर लगने वाले समय को कम करेगा। बयान के मुताबिक, एलपीएमएस सरकारी एजेंसियों और निजी ऑपरेटरों सहित सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा। इससे काम में होने वाली देरी थमेगी। इसके साथ ही परिचालन दक्षता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह प्रणाली कार्गो और यात्रियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित, पूरी तरह डिजिटल वर्कफ्लो प्रदान करेगी। इसमें स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्लेटफार्मों से जुड़ाव- गृह मंत्रालय ने कहा कि एलपीएमएस को देश के प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ जोड़ा गया है। यह सिस्टम मोटर वाहन इकोसिस्टम के साथ एकीकृत होकर काम करेगा। इस जुड़ाव से अंतर-संचालनीय, कुशल और पारदर्शी सीमा प्रबंधन संभव हो सकेगा।

स्मार्ट बॉर्डर का संकल्प

मंत्रालय के अनुसार, यह पहल नरेंद्र मोदी सरकार के स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति संकल्प को दर्शाती है। तकनीक के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में पारदर्शिता आएगी। सुरक्षा और दक्षता को मजबूती मिलेगी। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्र के रणनीतिक फोकस को दिखाता है। यह कदम देश में व्यापार सुगमता, कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

सूरत में ज्वेलरी फैक्टरी में बड़ा हादसा

जहरीली गैस से चार मजदूरों की मौत

नई दिल्ली (ए)। सूरत में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना गुजरात के सूरत शहर के अश्विनी कुमार इलाके में स्थित एक ज्वेलरी निर्माण इकाई में हुई, जहां मजदूर सेप्टिक टैंक की सफाई का काम कर रहे थे।

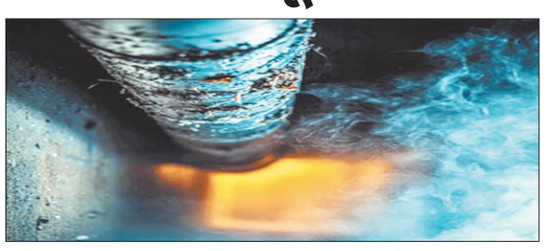

पुलिस के अनुसार, जिस टैंक की सफाई की जा रही थी, उसमें आभूषणों की सफाई प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा और रासायनिक अवशेष जमा होते हैं। इस टैंक की सफाई और रखरखाव हर दो महीने में किया जाता है। रविवार सुबह एक सुपरवाइजर और तीन मजदूर टैंक के अंदर उतरे थे। टैंक में मौजूद जहरीली गैस के कारण सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। सभी चारों लोगों को टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जोन-1 के पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मजदूरों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। यह भी पता चला है कि सुपरवाइजर ने टैंक में उतरने से पहले फायर ब्रिगेड को फोन किया था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी, हालांकि शुरुआती तौर पर दम घुटने और जहरीली गैस के प्रभाव को मौत का कारण माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि हादसे के लिए किसकी लापरवाही जिम्मेदार है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी और यह देखा जाएगा कि सुरक्षा संबंधी कौन-कौन से नियम लागू होने चाहिए थे और वास्तव में उनका पालन किया गया था या नहीं।

ये शर्मनाक है: राम मंदिर चंदे पर अखिलेश ने उठाए सवाल

करोड़ों की गड़बड़ी का किया दावा; मांगी कोर्ट की दखल

लखनऊ (ए)। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दान से करोड़ों रुपये गायब होने की खबरें सामने आई हैं। यादव ने अदालत से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है।

ये बेहद शर्मनाक है, चुप्पी पर उठ रहे सवाल- अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसे दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बेहद संवेदनशील बताया।

यादव ने कहा कि यह स्थिति मंदिर ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि राम मंदिर को दिए गए दान से करोड़ों रुपये गायब होना बहुत संवेदनशील खबर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मंदिर ट्रस्ट और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध प्रतीत होती है। पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने इस कथित विसंगति को सार्वजनिक चिंता का विषय बताया।

यूपी में चोर समझकर ग्रामीणों ने आरक्षक को पीटा, गंभीर

सिविल ड्रेस में वांटेड आरोपी को पकड़ने गई थी टीम

रायपुर। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में वांटेड आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश के कौशांबी पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने चोर समझ लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। घटना में एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाई। मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह मामला कोखराज थाना क्षेत्र के ईचौली गांव का है। जानकारी के अनुसार, देवनगर थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में तीन वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आरोपियों में आकाश, शिवम केशरवानी और उसका एक अन्य साथी शामिल हैं। इन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के ईचौली गांव पहुंची थी।

पूर्व सीएम एमके स्टालिन का बड़ा दावा: कहा-

तमिलनाडु में टीवीके सरकार पर संकट तीन महीने भी चलना मुश्किल

ऐतिहासिक बदलाव और छह दशक का रिकॉर्ड

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जबरदस्त उबाल है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की नई टीवीके सरकार तीन महीने भी नहीं चल पाएगी। मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय के नेतृत्व वाली यह सरकार शुरुआत से ही चौतरफा घिरी हुई है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में इसी साल मई के महीने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला था। अभिनेता से नेता बने सी. जोसफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पिछले 60 साल में यह पहली बार हुआ है जब तमिलनाडु में द्रमुक (डीएमके) या अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) से इतर किसी तीसरे दल की सरकार बनी है।

कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ

अपने इस तीखे राजनीतिक हमले के बीच एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को अनुशासन की सीख भी दी। उन्होंने दल-बदल कर आए नेताओं से साफ कहा कि वे अपनी पुरानी पार्टी की बुराई न करें। उन्होंने द्रमुक के संस्थापक सीएन अन्नादुरई के एक प्रसिद्ध कथन का जिक्र किया। स्टालिन ने कहा कि अन्ना ने हमेशा सिखाया है कि विरोधी के बगीचे के चमेली के फूल में भी खुशबू होती है।

अग्निमित्रा पॉल ने धृतराष्ट्र से की ममता बनर्जी की तुलना

मदरसों को बताया घुसपैठियों का ठिकाना

सिलीगुड़ी (ए)। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को मदरसों के चल रहे सर्वेक्षण का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कवायद जरूरी है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल आतंकवादियों और घुसपैठियों के लिए सुरक्षित अड्डा न बन जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्लिम छात्रों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।

अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस शासन के पिछले 15 वर्षों और उससे पहले वाम मोर्चा के 34 वर्षों के दौरान राज्य में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के प्रवेश को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा, पिछले 49 वर्षों में, हमने देखा है कि कैसे रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को राज्य में प्रोत्साहित किया गया और लाया गया। मंत्री पॉल ने कहा कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चे राज्य की विकास यात्रा का हिस्सा बनें और मदरसों में आधुनिक शिक्षा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे उस यात्रा का हिस्सा बनें, जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विकास के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाए। मुस्लिम बच्चे, चाहे वे महिला हों या पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, वैज्ञानिक और आईएफएस अधिकारी बनें। हम चाहते हैं कि वे उस टीम का हिस्सा बनें जो बंगाल और भारत को आगे ले जाएगी।

पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना- पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछे जाने पर पॉल ने कहा कि वह अटकलें नहीं लगाना चाहतीं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है।

विपक्ष पर भाजपा का तीखा हमला

पॉल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन अप्रासंगिक हो गया है और इसके घटक दलों में गहरे मतभेद हैं। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय टीएमसी कई टुकड़ों में बंटी हुई है। हमें नहीं पता था कि टीएमसी जल्द ही टुकड़े-टुकड़े गैंग बन जाएगी। उन्होंने गठबंधन में अन्य विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया। पॉल ने कहा, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद कह रहे हैं कि वह बीमार हैं और नहीं जाएंगे। स्टालिन कह रहे हैं कि डीएमके हिस्सा नहीं लेगी।

नगर मे व्यापारी बंधुओं को आ रही समस्याओं के संबंध मे जनदर्शन में कलेक्टर से मिले चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, रखी अपनी मांग

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज नगर इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मी साहू के नेतृत्व मे व्यापारियों ने जनदर्शन मे कलेक्टर कुलदीप शर्मा से मुलाकात कर व्यापार मे आ रही समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कर अपनी मांगे रखी जिनमें मुख्य रूप से बलौदाबाजार नगर मे संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों मे हाल फिलहाल मे आगजनी की घटनाएँ हुई हैं जिसमे त्वरित फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो जाने से व्यापारियों को कम नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फायर स्टेशन नगर से 8 कि.मी. दूर एवं उसके लिए पानी की आपूर्ति 15 कि.मी. दूर से होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा एवं कई गुना सामान की क्षति झेलनी पड़ी। इसके साथ ही बाजार मे चोरी की घटनाओं मे भी बेतहासा वृद्धि हुई है एवं कार्यवाही नही होने या आरोपियों के पकड़ मे ना आने

के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। बाजार एवं मुख्य मार्ग मे अतिक्रमण के कारण तथा पार्किंग की उचित व्यवस्था उपलब्ध ना होने के कारण लगातार व्यापार प्रभावित हो रहा है। अतः इन समस्याओं से व्यापारियों को छुटकारा दिलाने के लिए छत्तीसगढ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बलौदाबाजार के सदस्यों द्वारा कुछ मांगें महोदय के समक्ष रखी जा रही हैं। फायर स्टेशन बलौदाबाजार नगर क्षेत्र मे स्थापित किया जाए जिससे की आग लगने की स्थिति मे त्वरित पर्याप्त सहायता उपलब्ध हो सके साथ ही नगरपालिका बलौदाबाजार द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्काल टैंकर की व्यवस्था की जाए। नगर मे बढ़ते चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सभी चौक चौराहों व्यस्त मार्गों पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जांए बाजार मे रात्रि मे लगातार गश्ती वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही मवेशी बाजार भैंसा पसरा, पुराना बस स्टैंड, रामसागर तालाब जैसे संवेदनशील इलाकों मे पुलिस चौकी या बल की व्यवस्था की जाए। बाजार मे पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात को दुरूस्त करने के लिए मवेशी बाजार मे हुए बाउंड्रीवाल को पार्किंग जोन बनाया जाए। पूर्व मे सब्जी विक्रेताओं के लिए निर्मित 2 चबूतरे जिसमे शेड लगा हुआ है मे सब्जी विक्रेताओं का व्यवस्थापन। मुख्य मार्ग से ठेले शेड आदि को स्थाई रूप से हटाकर कब्जा मुक्त कर मार्ग के किनारे छोटे वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जाए जिससे की ग्राहकों को पार्किंग की समस्या का सामना ना करना पड़े। छत्तीसगढ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बलौदाबाजार के लिए बाजार के पास मे ही भूमि एवं भवन उपलब्ध कराया जाए जिससे की संगठन को व्यापारी ग्राहकों एवं शासन प्रशासन के मध्य समन्वय बैठाने मे आसानी हो सके। अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने कहा की चेंबर द्वारा पूर्व मे भी राजस्व मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, कलेक्टर दीपक सोनी को चेंबर के पूर्व अध्यक्ष जुगल भट्टर एवं सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति मे उक्त समस्याओं से अवगत कराया गया एवं मांग रखी जा चुकी है इसके बाद नई कार्यकारिणी के गठन के पश्चात भी इस संबंध मे ज्ञापन दिया गया और चर्चा की गई लेकिन अभी तक शासन प्रशासन से आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नही उठाया गया है। व्यापारियों एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा शासन प्रशासन को हर संभव मदद और सहयोग समय समय पर किया जाता रहा है। व्यापारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द आपके द्वारा संबंधित विभाग को आदेशित कर समाधान निकाला जाएगा एवं उचित ठोस कदम उठाएंगे। ऐसी उम्मीद है साथ ही थोक व्यापार के लिए जगह उपलब्ध कराने की भी मांग रखी जिससे की बलौदाबाजार के व्यापार को बढ़ाया जा सके। उक्त अवसर पर चेंबर के महामंत्री शिवप्रकाश तिवारी उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल पियूष मिश्रा कोषाध्यक्ष लक्ष्मेंद्र अग्रवाल मुख्य सलाहकार अभिषेक तिवारी एवं शिवम सतीश साहू उपस्थित रहे।

सार्थक ग्रीन धमतरी द्वारा पारंपरिक कुल्हड़ों में लस्सी सेवा, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक पहल

धमतरी। सार्थक ग्रीन धमतरी द्वारा भीषण गर्मी के बीच राहगीरों एवं नागरिकों के लिए पारंपरिक कुल्हड़ों में लस्सी सेवा का आयोजन किया गया। 20 व्यक्तियों के सहयोग से किए गए इस आयोजन का उद्देश्य जनसेवा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली के प्रति जनजागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर लगभग 200 किलोग्राम दही से तैयार शुद्ध, स्वादिष्ट एवं शीतल लस्सी का वितरण कुल्हड़ों में किया गया, जिससे बड़ी संख्या में राहगीरों एवं नागरिकों ने राहत एवं संतोष व्यक्त किया। यह सेवा दो घंटे से अधिक समय तक निरंतर संचालित रही, जिसमें लगभग 2500 पारंपरिक कुल्हड़ों का उपयोग किया गया। ये कुल्हड़ उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं तथा इन्हें अच्छी तरह साफ करके घरों में कई दिनों तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को और अधिक बल मिलता है। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. सरिता दोशी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की प्रेरणा उन्हें पूर्व जिलाधीश नम्रता गांधी के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से प्राप्त हुई । साथ ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित सभी नागरिकों एवं सहयोगियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई, जिसमें सभी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, वृक्षारोपण बढ़ाने तथा प्रकृति संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। इस पुनीत मानव सेवा अभियान में सार्थक ग्रीन टीम ने छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड (छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग) द्वारा प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया । विशेष रूप से बोर्ड के प्रबंध संचालक जय प्रकाश मौर्य एवं प्रबंधक साकेत कुमार राजपुरिया के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

धमतरी को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात, नया जिला अस्पताल जल्द होगा शुरू

धमतरी। जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है वर्षों से जिस ट्रॉमा सेंटर और अत्याधुनिक जिला अस्पताल की मांग की जा रही थी वह अब जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है अस्पताल भवन पूरी तरह तैयार है आधुनिक मेडिकल उपकरण भी पहुंच चुके हैं इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने नए अस्पताल भवन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। धमतरी को जल्द ही एक अत्याधुनिक जिला अस्पताल की सौगात मिलने वाली है नए अस्पताल भवन में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों जांच कक्षों और चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया इस अस्पताल की

सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यहां करीब 130 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी जहां दिन में लगभग 1000 लोगों तक की जांच की जा सकती है वहीं जांच रिपोर्ट मरीजों को सीधे उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी जिससे उन्हें बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और इलाज के लिए लोगों को भटकना न पड़े इसी सोच के तहत इस अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है यहां सामान्य बीमारियों के साथ साथ किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध होगी। धमतरी का जिला अस्पताल पहले से ही कांकेर और बस्तर जैसे क्षेत्रों के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र रहा है नए अस्पताल के शुरू होने के बाद इसकी क्षमता और बढ़ेगी जिससे दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा।

ग्राम पंचायत भूमिया में 'सुशासन तिहार' का समापन, मंत्री टंक राम वर्मा ने दी 2 करोड़ के विद्युत सब-स्टेशन की सौगात

तिल्दा-नेवरा। ग्राम पंचायत भूमिया में 'सुशासन तिहार' के पांचवें एवं अंतिम शिविर का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस मेगा शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी समस्याओं के निराकरण और मांग पत्र लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे।

मंत्री और सांसदों की रही गरिमामयी उपस्थिति

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सभा सांसद लक्ष्मी वर्मा उपस्थित रहे, पूर्व जिला महामंत्री अनिल अग्रवाल, जिला पंचायत सभापति शैल महेंद्र साहू, जिला पंचायत सभापति स्वाति वर्मा, जिला पंचायत रायपुर सीईओ कुमार विश्वरंजन, एसडीएम तिल्दा आशुतोष देवांगन, जनपद सीईओ रवि कुमार और भूमिया सरपंच मोहित कुमार यदु सहित 17 पंचायतों के सरपंच व सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

विद्युत सब-स्टेशन की बड़ी घोषणा

शिविर में ग्रामीणों की मांग पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्य अतिथि मंत्री टंक राम वर्मा ने ग्राम पंचायत भूमिया में लो-वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से नए विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।

973 आवेदनों में से 165 का मौके पर निराकरण

शिविर में मांग एवं शिकायत के कुल 973 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 165 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष बचे 808 लंबित आवेदनों को आगामी 1 माह के भीतर निराकृत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राही लाभान्वित

मंच से अतिथियों द्वारा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत चेक और सामग्रियों का वितरण किया गया। 06 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी और प्रमाण पत्र सौंपे गए। 11 'लखपति दीदियों' को प्रमाण पत्र, 07 को स्वीकृति पत्र और 04 महिला सदस्यों को चेक वितरित किए गए। 07 श्रम कार्ड, नोनी सशिक्तीकरण योजना के तहत 20-20 हजार के चेक और मिनी माता महतारी जतन योजना की राशि बांटी गई। 08 आयुष्मान कार्ड, 10 मनरेगा जॉब कार्ड, 10 स्वामित्व कार्ड, 06 राशन कार्ड, 10 को बीज (ढेंचा/मूंग) और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को छड़ी प्रदान की गई।

जिला प्रशासन ने 5 जेसीबी और 32 ट्रैक्टर सहित दस हाईवा पर कार्रवाई

अवैध रेत खदानों पर बड़ी कार्यवाही

धमतरी । धमतरी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है जिले के अलग अलग रेत खदानों में अवैध रूप से मशीनों से रेत निकालने की शिकायत पर प्रशासन ने छापा मारते हुए पांच जेसीबी और 32 ट्रैक्टर दस हाईवा पर कार्रवाई की है साथ ही एक रेत भंडारण को भी निरस्त किया गया है इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन को खरेंगा रेत खदान सहित जिले के कई खदानों में नियमों के विपरीत मशीनों से रेत उत्खनन किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद प्रशासनिक और खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की जहां पांच जेसीबी और 32 ट्रैक्टर दस हाईवा अवैध उत्खनन में लगे पाए गए। टीम ने सभी वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया। इसके अलावा एक रेत

भंडारण की अनुमति भी निरस्त कर दी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अवैध रूप से रेत उत्खनन परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी प्रशासन की इस सख्ती के बाद अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।

विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है सकारात्मक मीडिया, पत्रकार सम्मान समारोह आज

तिल्दा-नेवरा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ब्रह्माकुमारीज़ तिल्दा के मीडिया प्रभाग द्वारा गुरुवार को सायं 5 बजे से 7 बजे तक पत्रकार सम्मान समारोह एवं विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विषय वैश्विक शांति की आवश्यकता : मीडिया की भूमिका रखा गया है, जिसमें वर्तमान समय में विश्व शांति स्थापित करने में मीडिया की जिम्मेदारियों एवं योगदान पर सार्थक चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्माकुमारीज़ सेवाकेंद्र, सुना अस्पताल के पास, खरोरा रोड, तिल्दा में किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के पत्रकारों, मीडिया प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों के अनुसार आज विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों, तनाव और वैचारिक विभाजन से गुजर रहा है। ऐसे समय में मीडिया केवल समाचारों का प्रसार करने वाला माध्यम नहीं, बल्कि समाज

को सकारात्मक दिशा देने वाला एक सशक्त मंच भी है। यदि पत्रकारिता में सकारात्मकता, निष्पक्षता और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए तो वह सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक शांति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं के समाज निर्माण, जनजागरण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में दिए जा रहे योगदान का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही मीडिया जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक संवाद के माध्यम से यह विचार-विमर्श होगा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता किस प्रकार समाज में शांति, सदभाव और सकारात्मक परिवर्तन की वाहक बन सकती है। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्माकुमारीज़ तिल्दा के मीडिया प्रभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इसमें तिल्दा-नेवरा नगर पालिका की पार्षद रानी सौरभ जैन का विशेष सहयोग रहेगा। आयोजकों ने सभी पत्रकार बंधुओं एवं जागरूक नागरिकों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का लाभ लेने और विश्व शांति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

दर्पण वेलफेयर फाउंडेशन हिरमी द्वारा 50 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित

तिल्दा नेवरा। दर्पण वेलफेयर फाउंडेशन एवं राजपूत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हिरमी के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 50 दिनों का ग्रीष्मकालीन निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना तथा डिजिटल तकनीक की जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षकों द्वारा प्रोजेक्टर एवं टीवी स्क्रीन के माध्यम से प्रायोगिक तरीके से कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, टाइपिंग, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल शिक्षा एवं अन्य तकनीकी विषयों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें नजदीकी करीब 17 ग्रामों के बच्चे पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण में भाग लेकर नई तकनीकी जानकारी सीख रहे हैं। संस्था के पदाधिकारियों में तनमय सिंह राजपूत ने बताया कि लगातार विगत पांच वर्षों से ये आयोजन निःशुल्क किया जा रहा हैं इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं स्कूली छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उन्हें भविष्य के लिए तकनीकी व डिजिटल युग में सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाना है। क्षेत्रवासियों ने इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपयोगी पहल बताया।

जिले के 39 नवीन सहकारी समिति को मिला पीओएस मशीन, खाद वितरण शुरू

बलौदाबाजार। शासन की महत्वपूर्ण किसान हितकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के पुनगर्ठन योजना अंर्तगत जिले में 39 नवीन ग्रामीण सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है। सभी नवीन 39 सहकारी समितियो को खाद के सुगमतापूर्ण वितरण हेतु पीओएस मशीन प्रदाय किया गया है। पीओएस मशीन उपलब्ध होते ही सभी नवीन समितियों में किसानों को सुगम खाद-बीज़ का वितरण किया जा रहा है। नवीन गठित 39 सहकारी समितियों के 89 पंचायतों में 112 ग्रामो के 43639 किसानो को इससे लाभ हुआ है। किसानों को खेती किसानी के लिये सुगमता पूर्वक त्वरित एवं अपने गृह ग्राम के निकट ही खाद बीज एवं नगद ऋण प्राप्त हो रहा है जिससे किसानो में खुशी व्याप्त है। 39 नवीन समितियों में अभी तक 112 ग्रामों के 43639 किसानों को खाद प्रदाय हेतु 1876 टन का खाद का भंडारण एवं 353 टन खाद का वितरण के साथ कुल 48 करोड 99 लाख का ऋण वितरण किसानो को किया जा चुका है। खरीफ सीजन में जिले के किसानों को आवश्यकता अनुसार सहकारी समितियों से खाद बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।

विधवा पेंशन बंद होने से बढ़ी वृद्ध महिलाओं की परेशानी कलेक्टर से लगाई गुहार

धमतरी । धमतरी जिले में विधवा पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं कई महीनों से पेंशन राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर महिलाएं कुरूद के भूतपूर्व विधायक लेखराम साहू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचीं और कलेक्टर से गुहार लगाई महिलाओं का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से दवाई राशन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे महिलाओं और कांग्रेस नेता ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में विधवा महिलाओं को पिछले कुछ महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द पेंशन राशि जारी करने की मांग की है वहीं भूतपूर्व विधायक लेखराम साहू ने कहा कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन और प्रदर्शन करेगी इधर प्रशासन ने मामले का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को जल्द पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया है।

बेलमुंडी सहकारी समिति से 108 किसानों को वितरण किया गया खाद

सरायपाली। खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा प्रतिदिन खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की समीक्षा भी की जा रही है। जिला विपणन अधिकारी के अनुसार जिले की 159 सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा किसानों की मांग के अनुरूप लगातार वितरण किया जा रहा है। खरीफवर्ष के लिए जिले को 60 हजार 850 टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 16 हजार 294 टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 26.78 प्रतिशत है। वहीं किसानों को अब तक 7 हजार 720 टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। भंडारित उर्वरकों में

11 हजार 338 टन यूरिया, 1 हजार 928 टन डीएपी, 449 टन एनपीके तथा 1 हजार 496 टन एसएसपी शामिल हैं। जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में किसान नियमित रूप से खाद का उठाव कर रहे हैं। तोरेसिंहा सहकारी समिति बेलमुंडी के अंतर्गत अब तक 108 किसानों को खाद का वितरण किया गया है। गांव के किसान कमलेश ने बताया कि उन्हें आसानी से 8 बोरी यूरिया और 3 बोरी डीएपी प्राप्त हुआ। वहीं किसानों शरद और गुलाल ने भी बताया कि उन्हें बिना किसी परेशानी के डीएपी और यूरिया उपलब्ध हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग उर्वरक कंपनियों से अतिरिक्त रैक प्राप्त कर लगातार भंडारण बढ़ा रहा है, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही समितियों और निजी विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण भी कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा मांग और आपूर्ति की दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत सहकारी समितियों और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही पॉस मशीन के माध्यम से उर्वरक खरीदें तथा खरीद की रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को देने की भी अपील की गई।

विकास की नई इबारत लिख रहा बिलासपुर, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता : तोखन साहू

जनता के विश्वास को और मजबूत बना रहा सुशासन तिहार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

बिलासपुर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव सुशासन तिहार के अंतर्गत बिलासपुर के पुत्रीबाई स्कूल सामुदायिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय शहरी समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही ही वास्तविक सुशासन है। सुशासन तिहार ने शासन के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है। न्यायधानी बिलासपुर को उसकी पहचान और गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथियों ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 12 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से अरपा राम सेतु से शनिचरी रपटा तक सड़क, नाला एवं पिचिंग कार्य तथा 5 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से कुंदन पैलेस से सहारे गली होते हुए बस स्टैंड तक आरसीसी बॉक्स निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। कुल 18 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के लागत के इन विकास कार्यों से शहर की अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को और सशक्त बनाने का अभिनव अभियान है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रदेश विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। साहू ने कहा कि बिलासपुर आज तेजी से बदलती हुई न्यायधानी के रूप में उभर रहा है। फोरलेन सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में हो रहे प्रयास तथा कोपरा जलाशय का रामसर साइट के रूप में चयन इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। बिलासपुर के समग्र विकास के लिए आवश्यक हर सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और शासन के प्रति उसका बढ़ता विश्वास ही सुशासन तिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार ने शासन और आमजन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम तैयार किया है, जिससे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर को उसकी पहचान के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विगत दो वर्षों में जिले में 412 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत और संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की यह गति आगे भी जारी रहेगी और न्यायधानी को प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में शामिल किया जाएगा। साव ने पुत्रीबाई सामुदायिक भवन में बाउंड्रीवॉल एवं शौचालय निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की।

जिले में खाद-बीज की उपलब्धता संतोषजनक, किसानों को समय पर प्रदाय किया जा रहा कृषि आदान

कांकेर। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए जिले में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले में खाद एवं बीज के भंडारण तथा वितरण की स्थिति की समीक्षा के अनुसार वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान उपलब्ध है। उप संचालक कृषि जितेन्द्र कोमरा ने बताया कि विभाग द्वारा वर्तमान सत्र में किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप भंडारण एवं वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के लिए कुल 64560 मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें यूरिया 28060 मेट्रिक टन, डीएपी 10500 मेट्रिक टन, एनपीके 11000 मेट्रिक टन, एस.एस.पी. 9000 मेट्रिक टन तथा एमओपी 6000 मेट्रिक टन शामिल हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में यूरिया 15097.197 मेट्रिक टन, डीएपी 3752.625 मेट्रिक टन, एनपीके 8588.41 मेट्रिक टन, एस.एस.पी. 6368.25 मेट्रिक टन तथा एमओपी 3067.27 मेट्रिक टन उपलब्ध है। साथ ही सहकारी समितियों एवं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को उर्वरकों का सुचारू वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत् अब तक यूरिया 6193.635 मेट्रिक टन, डीएपी 1523.75 मेट्रिक टन, एनपीके 2889.67 मेट्रिक टन, एस.एस.पी. 2003.45 मेट्रिक टन तथा एमओपी 1098.15 मेट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। साथ ही विभाग द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की नियमित निगरानी कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिली बड़ी राहत, पहले चरण में 12 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 12 करोड़ रुपये

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए संग्रहण पारिश्रमिक (मजदूरी) दर में भारी बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, चरणपादुका योजना फिर से शुरू करके संग्राहकों को सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2026 के तहत छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिलना शुरू हो गया है। राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के अंतर्गत प्रथम चरण में 12 हजार 379 संग्राहकों के बैंक खातों में 12 करोड़ रुपये की राशि सीधे ऑनलाइन (डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की गई है। बीजापुर जिले की 28 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 45 लॉटों में कुल 40 हजार 716 संग्राहकों ने 65 हजार 430.359 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया है। शासन द्वारा निर्धारित 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से जिले के संग्राहकों को कुल 35.99 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया जाना है। इसके अलावा 500 गड्डी से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले संग्राहकों को शासन की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। भुगतान के पहले चरण में जिले की प्रमुख समितियों के बैंक खातों में राशि सीधे (डीबीटी के माध्यम से) जमा की गई है। प्राथमिक वनोपज समिति लाभान्वित संग्राहक हस्तांतरित राशि गुडमा समिति के 1,912 संग्राहकों को 1.95 करोड़ रुपये, कुटरू समिति के 937 संग्राहकों को 1.29 करोड़ रुपये, तोयनार समिति के 961 संग्राहकों को 1.20 करोड़ रुपये तथा बरदेला समिति के 1,023 संग्राहकों को 1.11 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा की गई है। इसके अलावा संतोषपुर, भैरमगढ़, माटवाड़ा, कोडोली, नैमेड़, भद्रकाली और चेरपल्ली सहित अन्य समितियों के संग्राहकों को भी लाखों रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। शेष समितियों में संग्रहित मात्रा का सत्यापन और ऑनलाइन एंट्री का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके पूरा होते ही सभी पात्र संग्राहकों को भुगतान कर दिया जाएगा।झ वनोपज आधारित आजीविका

दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम विष्णुदेव साय

विकास, विश्वास और सुशासन का सेतु बना कोण्डापल्ली का बेली ब्रिज'

बीजापुर। जहां कभी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में चुनौती बनती थीं, वहां आधुनिक अधोसंरचना नए अवसरों के द्वार खोल रही है। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचकर बीजापुर-पूवर्ती मार्ग पर निर्मित बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल की निर्माण तकनीक, उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका की जानकारी लेते हुए इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि वे दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मजबूत माध्यम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो।

कम समय, कम लागत और अधिक मजबूती की तकनीक

भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यह बेली ब्रिज बीजापुर-पूवर्ती सड़क परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बेली ब्रिज पारंपरिक पुलों की तुलना में अधिक किफायती, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण सामान्य पुलों की अपेक्षा लगभग पांच गुना कम लागत में किया जा सकता है तथा इन्हें मात्र एक माह के भीतर तैयार किया जा सकता है। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

बीजापुर में 21 बेली ब्रिज बने विकास के वाहक

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले में अब तक 21 बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इन पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों तक आवागमन सुगम हुआ है तथा लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में बड़ी राहत मिली है। इन संरचनाओं ने क्षेत्र में विकास और जनसेवाओं के विस्तार को नई गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के श्रमिक और युवा ही विकास यात्रा के वास्तविक निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने श्रमिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए।

बदलते बस्तर की नई पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में अधोसंरचना विकास के माध्यम से नई संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। कोण्डापल्ली का यह बेली ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और सुशासन का सशक्त प्रतीक है। यह उस नए बस्तर की पहचान है, जहां विकास अब दूरस्थ गांवों और दुर्गम अंचलों तक मजबूती से पहुंच रहा है तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

जेसीबी मशीन से कराए तालाब गहरीकरण के मस्टरोल में नाम डालने एक एक हज़ार रुपए की मांग

गरियाबंद। देवभोग विकासखंड के ग्राम पंचायत मौखगुड़ा में मनरेगा के तहत स्वीकृत रयाडोंगरी पहाड़ के समीप तालाब गहरीकरण जेसीबी मशीन से कराकर पंचों के द्वारा चयनित और एक एक हज़ार रुपए देने की हामी भरने वाले मजदूरों का नाम मस्टरोल में नाम डाला जा रहा है जिसकी शिकायत लालेन्द्र कश्यप ने आज मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी शिवकुमार नारंगे से करते हुए बताया कि रताडोंगरी पहाड़ के समीप तालाब पर बीते एक सप्ताह से जेसीबी मशीन से खुदवाई किया गया और एक एक हज़ार देने पर हामी भरने वाले मजदूरों का नाम चढ़ाया जा रहा है बीते हफ्ता ऐसे ही मजदूरों का नाम मस्टरोल में उल्लेख है जो एक घमेला मिट्टी नहीं निकले है सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाए और मजदूरी ले लिया हालाँकि उक्त राशि से एक एक हज़ार पंचायत के जिम्मेदारों को देने पर हामी हुआ है जिन्होंने एक हज़ार देने से मना कर दिया उन्हें तालाब गहरीकरण में मजदूरी देने से साफ-साफ इंकार कर रहे है, जिसे देख तालाब गहरीकरण के कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रताडोंगरी के समीप तालाब गहरीकरण का कार्य मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन कराया जाना दुर्भाग्य है, क्योंकि पहले की तुलना वर्तमान में मनरेगा से मजदूरी नहीं मिल पा रहा हैं। बावजूद इसके जेसीबी मशीन से काम कराकर मजदूरों के हक में डाका डालने का दिन दहाड़े जिम्मेदारों के निगरानी में हो रहा है। इस बीच मनरेगा अधिकारी शिवकुमार नारंगे जेसीबी मशीन से काम करने और रोजगार नहीं देने की शिकायत पर भड़कते रोजगार सहायक दूरभाष के माध्यम से जमकर फटकार लगाया। साथ ही शिकायतकर्ता लालेन्द्र कश्यप को तालाब गहरीकरण कार्य में रोजगार दिलाने के साथ साथ शिकायत की जांच कर उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है।

जाबकार्डधारियो को काम दिलाने की माँग

हाल फिलहाल में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण जैसे अन्य रोजगारमूलक कार्य स्वीकृत हुआ हैं, उसमें भी चेहरा देख-देख अपने चहते को मजदूरी दिया जा रहा है। ऐसे में कई मजदूर मजदूरी से वंचित हो चुके है। इसलिए स्थानीय अधिकारियों गुहार लगाते सभी जाबकार्डधारियो को रोजगार मूलक काम से जोड़ने की मांग कर रहे है। क्योंकि मनरेगा में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही है, इसलिए मनरेगा काम करते है या फिर पलायन की ओर रूख कर लेते हैं।

जेसीबी मशीन से कराए कार्य की जांच

तालाब गहरीकरण को देख्र प्राथमिक तौर पर आराम से कहा जा सकता है कि जेसीबी मशीन से खुदवाया गया है। मतलब सैकड़ों मजदूरों का काम को चंद घंटे में करा लिया और मजदूरों को कुछ दिन का मानव दिवस देकर स्वीकृत राशि खत्म होने का पल्ला झाड़ लेंगे। इस स्तिथि में हफ्ता भर का काम मिलना भी मुश्किल है। इसलिए जेसीबी मशीन से कराए गए गहरीकरण कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद कार्रवाई किया जाए, ताकि आगामी समय मजदूरों के मजदूरी में ना मार सके।

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 के तहत आयोजित बैठक में हितग्राहियों को दी गई व्यवसाय संचालन, ऋण सुविधा एवं पर्यटन संभावनाओं की जानकारी

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 के अंतर्गत नए हितग्राहियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उददेश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पर्यटन सूचना केंद्र जगदलपुर द्वारा जिला पंचायत बस्तर के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में इच्छुक हितग्राहियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए हितग्राहियों को होमस्टे व्यवसाय की बारीकियों से परिचित कराना, उन्हें पर्यटन आधारित स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना तथा छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति जागरूक करना था। इस सराहनीय पहल से बस्तर में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होने की प्रबल उम्मीद है। बैठक के दौरान उपस्थित हितग्राहियों से उनके प्रस्तावित होमस्टे के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। अधिकारियों ने विशेष रूप से यह जाना कि हितग्राही किस स्थान पर होमस्टे स्थापित करना चाहते हैं और उस क्षेत्र के आसपास कौन-कौन से पर्यटन स्थल या आकर्षण मौजूद हैं। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध क्षेत्रों में होमस्टे विकसित होने से पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस अवसर पर हितग्राहियों को होमस्टे व्यवसाय के सफल संचालन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। उन्हें मुख्य मुख्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अतिथि सत्कार के लिए पर्यटकों का स्वागत और आतिथ्य प्रबंधन, स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन, सुविधाएं व मार्केटिंग के रूप में पर्यटकों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं और डिजिटल प्रचार-प्रसार के तरीके, छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 के प्रावधान, पात्रता शर्तें एवं आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी दी। उन्होंने हितग्राहियों को ऋण सुविधा, ब्याज अनुदान तथा बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया और आश्वस्त किया कि शासन की सहायता तथा बैंकिंग सहयोग से इच्छुक हितग्राही अपने होमस्टे व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकते हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला पंचायत बस्तर के सहायक परियोजना अधिकारी, तपन डे ने हितग्राहियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जनजातीय संस्कृति एवं पर्यटन स्थलों की विविधता होमस्टे व्यवसाय के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है।

विधायक नीलकंठ टेकाम के प्रयासों से सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज को मिली ऐतिहासिक सौगात

केशकाल। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान विधायक नीलकंठ टेकाम की दो महत्वपूर्ण मांगों पर तत्काल सहमति प्रदान करते हुए केशकाल में सर्व आदिवासी समाज के लिए बहुउददेश्यीय काम्प्लेक्स सह विश्राम गृह तथा विश्रामपुरी में गोंडवाना समाज के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से गोंडवाना भवन सह कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की। बताया जा रहा है कि यह मांग लंबे समय से क्षेत्र की जनता एवं आदिवासी समाज द्वारा उठाई जा रही थी, लेकिन अब तक इसे मूर्त रूप नहीं मिल पाया था। विधायक नीलकंठ टेकाम के लगातार प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री ने मंच से ही दोनों भवनों की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है।

जानिए क्या है बहुउद्देश्यीय मल्टीकाम्प्लेक्स

इस संबंध में विधायक नीलकंठ टेकाम ने बताया कि यह कोई सामान्य सामुदायिक भवन नहीं होगा, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुउददेशीय कॉम्प्लेक्स सह विश्राम गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन के सबसे निचले तल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और समाज के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके ऊपर के तल में आदिवासी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनी केंद्र तथा आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। भवन के तीसरे तल में विश्रामगृह एवं विशाल मीटिंग हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग आदिवासी समाज के साथ-साथ अन्य समाजों के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए कर सकेंगे। विधायक टेकाम ने कहा कि इन भवनों का उद्देश्य केवल समाज विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सर्वसमाज के उपयोग के लिए तैयार किए जाने वाले आधुनिक सामाजिक केंद्र होंगे।

भाजपा जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों ने भी जताया आभार

बता दें कि इन दोनों भवनों के लिए विधायक नीलकंठ टेकाम के साथ साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सेवकराम नेताम एवं सभी 6 मंडल अध्यक्षों ने भी सीएम साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिसमें केशकाल- लंबोधर सलाम, विश्रामपुरी- मनाराम मरकाम, बडेराजपुर- लालाराम मरकाम, बड़ेडोंगर- महेंद्र सलाम, फरसगांव- धनराज पांडे, धनोरा- संतोष सिन्हा शामिल हैं।

विधायक टेकाम ने समाज की ओर से जताया आभार

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन भवनों के निर्माण से जहां आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का स्थायी केंद्र मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन संसाधन और आम जनता के लिए सामाजिक गतिविधियों का एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा।

दंतेवाड़ा जेल के अशासकीय संदर्शक पद हेतु जयदीप माकन नियुक्त

किरंदुल। छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 815(1) के तहत जिला जेल दंतेवाड़ा में अशासकीय संदर्शकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।इस संबंध में उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से प्रस्तावित नामों की सूची संबंधित विभाग को प्रेषित की गई हैं। जिसमें किरंदुल-बचेली क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जयदीप माकन को अशासकीय संदर्शक पद हेतु नियुक्ति दी गई हैं। जयदीप माकन लंबे समय से क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों एवं जनसरोकारों से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते उनके नाम को अशासकीय संदर्शक के लिए नामित किया गया हैं।

सालों बाद मलांगीर जलप्रपात में लौट रही रौनक,पर्यटकों की लग रही भीड़

किरन्दुल। बैलाडिला की लौह अयस्क पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित मलांगीर जलप्रपात कई वर्षों बाद नई पहचान के साथ सामने आया हैं। कभी नक्सलियों के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अब पर्यटकों की चहल-पहल दिखाई देने लगी हैं। गर्मी की छुटिटयों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे है और प्राकृतिक सौदर्य का आनंद ले रहे हैं। लंबे समय तक लाल आतंक के साए में छिपा रहा यह जलप्रपात अब दंतेवाड़ा जिले के उभरते पर्यटन स्थलों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा हैं। वर्ष 2004 में नक्सलियों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था।मलांगीर जलप्रपात के नाम पर ही 'मलांगीर एरिया कमेटी' बनाई गई थी।इसके बाद जनताना सरकार की गतिविधियां बढ़ती गई और क्षेत्र आम लोगों की पहुंच से दूर होता चला गया। सुरक्षा कारणों से लोग यहां आने से कतराते थे और यह खूबसूरत पर्यटन स्थल धीरे-धीरे गुमनामी में खो गया।वर्ष 2022 में हिरोली के डोकापारा में पुलिस कैंप खुलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन क्षेत्र में छिटपुट नक्सली गतिविधियां जारी रहीं। 31 मार्च 2026 को मलांगीर एरिया कमेटी के समाप्त होने के साथ ही क्षेत्र में स्थायी शांति का माहौल बना और जलप्रपात एक बार फिर लोगों के लिए खुल गया।मलांगीर के सुंदर जलप्रपात एवं वादियों का आनंद उठाने पहुंचें सैलानियों ने बताया कि मलांगीर जलप्रपात में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अगर जिला प्रशासन अभी ध्यान दे तो यह बस्तर का नया टूरिज्म हॉटस्पॉट बन सकता हैं। जिससे लोकल रोजगार बढ़ेगा, आदिवासियों की आमदनी बढ़ेगी और नक्सलवाद की वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ यहां स्वच्छता की चुनौती भी सामने आने लगी है। जलप्रपात परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा, पानी की बोतलें और शराब की खाली बोतलें फेंके जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो यह प्राकृतिक धरोहर प्रभावित हो सकती हैं। वहीं सुविधाओं के विस्तार की तैयारी में जिला प्रशासन द्वारा की जा रहीं हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए फेंसिंग, प्रवेश द्वार, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम पुरुष एवं महिला शौचालय, डस्टबिन तथा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए नई सीढ़ियों का प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया हैं।

संपादकीय

बंगाल में चुनाव बाद फिर सुलगा सियासी संग्राम

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बावजूद चुनाव बाद हिंसा और राजनीतिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर हमलों, बढ़ते राजनीतिक तनाव और कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों ने राज्य की शासन व्यवस्था पर नई चिंता खड़ी कर दी है।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि यह बदलाव केवल सत्ता के स्तर पर हुआ है, जमीनी हकीकत अब भी वही है। राज्य पहले की तरह ही चुनाव बाद की हिंसा और बदले की कार्रवाइयों में फंसा हुआ है। टीएमसी नेताओं पर हालिया हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पहले पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में निशाना बनाया गया। पार्टी इस मुद्दे को अदालत ले जाने और लोकसभा स्पीकर के सामने उठाने की तैयारी में है। इसके बाद, टीएमसी के चीफ विप कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली जिले में उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन पर हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस इन हमलों के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि ममता शासन के खिलाफ लोगों का दबा गुस्सा अब बाहर निकल रहा है।

हालांकि राजनीतिक हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। राज्य ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है और यह बदलाव राजनीतिक परिदृश्य में भी दिखना चाहिए। भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाया था। अब सरकार में होने के नाते सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर आती है। किसी को भी किसी भी वजह से कानून हाथ में लेने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव बाद हिंसा बंगाल की बहुत पुरानी बीमारी है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी हिंसा के सैकड़ों केस दर्ज किए गए थे।

तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1900 से ज्यादा मामलों की जांच की थी। इसमें स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इससे न तो 2023 के पंचायत चुनाव और न ही 2024 के आम चुनावों में कोई सबक लिया गया। इस बार भी चुनाव परिणाम घोषित होते ही कई जगह से तोड़फोड़, मारपीट की खबरें आईं। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई। रिजल्ट आने के तीन दिन बाद ही बंगाल पुलिस ने 200 से ज्यादा केस दर्ज कर 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अपने नेताओं पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने प्रदर्शन किया। उसके और सत्ताधारी भाजपा के बीच तनाव बना हुआ है। इसका असर शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे कार्यकर्ताओं तक दिख रहा है। कानून-व्यवस्था के लिहाज से यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार और विपक्ष के बीच अगर ऐसे ही टकराव चलता रहा, तो शासन से जुड़े कामकाज पर असर पड़ेगा।

'शिंदे फॉर्मूला' बंगाल तक पहुंचा! दीदी की टीएमसी में बिखराव के मिलने लगे संकेत

(सुधांशु माहेश्वरी)

असल में महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। इस महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई और बीजेपी को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक और किरदार था। वह था एकनाथ शिंदे। बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने को राजी नहीं थे।

टीएमसी में जारी बवाल में इस समय कुछ अहम पहलू दिखाई दे रहे हैं। नाराज विधायक, ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई और इस्तीफों का सिलसिला।पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार उसने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, बल्कि बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी की टीएमसी को करारी शिकस्त दी। चुनाव में बीजेपी 208 सीटें जीतने में सफल रही जबकि टीएमसी का आंकड़ा 80 सीटों पर सिमट गया। बाद में दो विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में अब उनके पास विधानसभा में मात्र 78 सीटें हैं।

इस करारी शिकस्त के बाद मंथन करने के लिए टीएमसी ने तीन बार बैठक बुलाई। 6 मई को बैठक बुलाई गई तो 10 विधायक पहुंचे ही नहीं। फिर 19 मई को बैठक बुलाई गई तो 35 विधायक नदारद रहे। उसके बाद 31 मई को बुलाई गई बैठक में तो सबसे बड़ा खेल हुआ और 80 में से 60 विधायक मीटिंग में पहुंचे ही नहीं।

इसके ऊपर ममता की टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी भी लग चुकी है। टीएमसी प्रवक्ता बिस्वजीत देब ने इस्तीफा दिया है। शांतनु सिंह, अभिजीत मजूमदार, काकोली घोष और अरुप चक्रवर्ती ने भी अपना पद छोड़ दिया है। इसके अलावा डायमंड हार्बर से 8 पार्षदों का इस्तीफा हुआ है। चंदननगर से 30 पार्षद, भाटपाड़ा से 30, गारुलिया से 18, हलिशहर से 16, उत्तर बैरकपुर से 15 और कांचरापाड़ा से 14 पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं।

इन इस्तीफों के अलावा ममता बनर्जी ने उलूबेरिया से विधायक ऋ्रब्रत बनर्जी और एंटाली से विधायक संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया। आरोप लगा कि दोनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। लेकिन असल विवाद यह था कि इन दोनों ही विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष से जुड़े प्रस्ताव और उस पर लिए गए हस्ताक्षरों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। संदीपन साहा तो यहां तक कह चुके थे कि इसमें ऐसे विधायकों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं जो असल में बैठक में शामिल तक नहीं हुए थे। इन आरोपों के बाद ही दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया गया।

विधायकों का नदारद होना, कुछ को निष्कासित कर देना और लगातार इस्तीफों का सिलसिला इस बात की ओर जरूर इशारा करता है कि टीएमसी में इस समय सब कुछ 'ऑल इज वेल' नहीं है।

मीडिया की एक रिपोर्ट दावा करती है कि कोलकाता के 'विधायक हॉस्टल' में टीएमसी नेताओं की एक सीक्रेट बैठक हो चुकी है। इस बैठक में निष्कासित विधायक के साथ-साथ कई असंतुष्ट नेता शामिल हुए और टीएमसी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव और नए राजनीतिक विकल्पों को लेकर चर्चा की गई।

बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद पार्टी को कमजोर करने जैसी साजिशों के आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने की एक संगठित साजिश चलाई जा रही है। ममता का यह कहना ही बता रहा है कि जमीन पर असंतोष है और उन्हें भी इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि क्या टीएमसी टूट जाएगी।

टीएमसी में जारी बवाल में इस समय कुछ अहम पहलू दिखाई दे रहे हैं। नाराज विधायक, ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई और इस्तीफों का सिलसिला। जानकार इस पैटर्न की तुलना महाराष्ट्र से करने लगे हैं जहां 2022 में एकनाथ शिंदे ने भी एक बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने शिवसेना में दो फाड़ कर दी थी और कई विधायकों को अपने साथ लेकर पूरी पार्टी पर कब्जा जमा लिया था।

असल में महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। इस महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई और बीजेपी को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया।

लेकिन उस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक और किरदार था। वह था एकनाथ शिंदे। बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने को राजी नहीं थे।

इसके बाद 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए और पता चला कि एकनाथ शिंदे और कुछ दूसरे विधायक मुंबई से बाहर जा रहे हैं। फिर खबर आई कि वे गुजरात के सूरत पहुंच चुके हैं। अगले ही दिन कई विधायकों को लापता बताया गया। उद्धव ठाकरे ने खतरा देखते हुए आपात बैठक बुलाई, लेकिन कई विधायक पहुंचे ही नहीं। यहीं से संकेत मिल चुके थे कि शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है।

इसके बाद 22 जून को शिंदे गुट असम के गुवाहाटी पहुंच गया। विधायकों की संख्या वहां बढ़ती गई। दावा किया गया कि 40 शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। फिर 22 से 28 जून तक दावों का खेल चलता रहा। शिंदे गुट की तरफ से लगातार कहा गया कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है और वह सरकार में नहीं बने रह सकते।

फिर 29 जून को फ्लोर टेस्ट की नौबत आई, लेकिन उसके ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। फिर 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। तब देवेंद्र फडनवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया।

सरकार बना ली गई थी, लेकिन असली शिवसेना पर कब्जा करना बाकी था। ऐसे में यह मामला चुनाव आयोग के पास चला गया, जिसने 8 अक्टूबर 2022 को शिवसेना के धनुष-बाण वाले चुनाव चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया। तब दो शिवसेना अस्तित्व में आईं। एक का नाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) रखा गया और दूसरी का नाम बालासाहेबांची शिवसेना यानी शिंदे गुट।

फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं असली शिवसेना को लेकर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया और मामला चुनाव आयोग के पास ही रहा।

फिर 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना घोषित कर दिया। धनुष-बाण वाला चुनाव चिन्ह भी उनके खाते में गया। इस तरह एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना पर अपना कब्जा कर लिया और उद्धव ठाकरे अलग-थलग पड़ गए। जानकार इसी को महाराष्ट्र का 'शिंदे फॉर्मूला' बताते हैं जहां सबसे पहले बागी विधायकों की नाराजगी को हवा दी जाती है, फिर उन्हें पक्ष बदलने के लिए मनाया जाता है और आखिर में सबसे बड़ा खेल होता है-दो फाड़।

अब इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया के सामने आकर अभिषेक बनर्जी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ दबी जुबान ममता बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। कई विधायकों का बैठकों से नदारद होना भी एक संकेत दे रहा है। इसी वजह से ऐसी अटकलें चल पड़ी हैं कि क्या 80 में से नदारद रहे 60 विधायक पार्टी को तोड़ भी सकते हैं?अभी इस सवाल का जवाब तो भविष्य की गर्भ में छिपा है, लेकिन ममता बनर्जी ने खतरे को भांपते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी है, लेकिन ममता ने भी तेवर दिखाते हुए दिल्ली कूच करने की चेतावनी दे दी है।यहां समझने वाली बात यह है कि सड़क पर उतरी ममता बनर्जी की असल पहचान भी यही है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी की एक स्ट्रीट फाइटर की इमेज है। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों ने उनकी छवि को मजबूत भी किया था। उन आंदोलनों के दम पर 34 साल के वामपंथी राज को भी खत्म किया गया था।

लेकिन तब की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। जब लेफ्ट से लड़ाई चल रही थी तब ममता की टीएमसी एकजुट थी। शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता भी ममता के साथ खड़े थे। लेकिन आज की चुनौतियां और आज का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। बंगाल में बीजेपी की सरकार है, टीएमसी के कई विधायक ममता और अभिषेक से नाराज बताए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई छिड़ चुकी है और लगातार हो रहे इस्तीफे सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं।

ममता की सड़क पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर टीएमसी को खड़ा कर पाएगी? इस सवाल का जवाब ही टीएमसी का भविष्य भी तय करेगा और ममता दीदी की आगे की रणनीति भी। (यह

जहां हम खड़े होते हैं, हमारी रीढ़ भी वहीं खड़ी होती है

(अभिषेक पाण्डेय)

ऐन रैंड का उपन्यास द फाउंटेनहेड मौलिकता और भेड़चाल के संघर्ष को सामने लाता है। हावर्ड रॉर्क आत्मनिर्भर सोच और सिद्धांतों का प्रतीक है, जबकि पीटर कीटिंग सामाजिक स्वीकृति का। जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन ने सिर्फ भारी-भरकम डायलॉग भर नहीं बोला था बल्कि कॉन्फिडेंस से भरे इंसानी मिज़ाज, आत्मसम्मान और चरम व्यक्तिवाद की एक ऐसी हुंकार भरी, जो सदियों के सामाजिक बंधनों को एक झटके में तोड़ देती है। जब हम इस डायलॉग की गहराई में उतरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह बात सीधे तौर पर उस वैचारिक धरातल से जुड़ती है, जिसे हमने कभी हावर्ड रॉर्क के मुंह से एकदम अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोलते हुए पढ़ा था - मैं किसी और के लिए नहीं जीता और न ही किसी और से ये उम्मीद करता हूं कि वह मेरे लिए जिए। आज से करीब 83 साल पहले ऐन रैंड ने अपने मशहूर उपन्यास ' द फाउंटेनहेड ' में यह फिलॉसफी पेश की थी। इस उपन्यास में दो मुख्य किरदार हैं - हावर्ड रॉर्क और पीटर कीटिंग जो आज के समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास हैं। दोनों ही आर्किटेक्ट हैं। रॉर्क एक ऐसा नायक है जो अपने सिद्धांतों और मौलिकता के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ पीटर कीटिंग है, जो समाज की नजरों में सफल होने के लिए अपनी मौलिकता को मारकर सिर्फ भेड़चाल का हिस्सा बनता है। रैंड के उपन्यास के हीरो हावर्ड रॉर्क को पसंद जरूर किया गया हो, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि हम सब धीरे-धीरे हावर्ड रॉर्क बनने का हौसला खो रहे हैं और पीटर कीटिंग की जमात में शामिल होते जा रहे हैं। अगर हम इस वैचारिक कशमकश को भारतीय संदर्भ में देखें, तो हमारी परवरिश की बुनियाद ही एक बिल्कुल अलग विरोधाभास पर टिकी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है 'जैसा देश, वैसा भेष'। पहली नज़र में यह बात सामाजिक सामंजस्य के लिए ठीक लगती है कि जहां रहो, वहां के सामाजिक माहौल में ढल जाओ लेकिन धीरे-धीरे यह मुहावरा हमारी मौलिकता यानी ओरिजिनैलिटी को कुचलने का एक औज़ार बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। सच तो यह है कि हमारी परवरिश कुछ इस तरह होती है कि हमें खुद को तलाशने के बजाय, समाज की कसौटियों पर फिट होने के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल जाओ, टीचर सवालों के जवाब लिखवा देती हैं और उम्मीद करती हैं कि सभी बच्चे उसी जवाब को रटा-रटाया, जस का तस लिखें एग्ज़ाम में। थोड़ा सा जवाब इधर-उधर हुआ नहीं, बच्चे ने वही बात अपनी भाषा में लिखी नहीं कि पूरे नंबर कट। स्कूल की कॉपियों से लेकर जीवन के फैसलों तक, हमारी तारीफ इस बात पर नहीं होती कि हमने नया क्या सोचा, बल्कि इस बात पर होती है कि हमने पहले से बनाए गए नियमों का कितनी खामोशी से पालन किया। यही भेड़चाल आगे चलकर हमारे करियर के फैसलों में दिखती है। बिना यह सोचे-समझे कि बच्चे का अपना टैलंट क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है, लाखों बच्चों को कोटा, इंजीनियरिंग या पीएससी की एक ही अंधी भट्टी में झोंक दिया जाता है। किसी एक कोचिंग का रिज़ल्ट आया नहीं कि पूरा समाज अपने बच्चों को उसी रास्ते पर दौड़ा देता है। हम पीटर कीटिंग पैदा करने वाली फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जहां युवा अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि समाज में रुतबा दिखाने के लिए करियर चुनते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि समाज की नजरों में क्या कमी है, उसे सुधारो न कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारे अंदर की ताकत क्या है। यह जो कंडीशनिंग है, वह इंसान को अपनी शर्तों पर जीने के बजाय दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देती है। इस तरह हम फॉलोअर्स की जमात तो तैयार कर लेंगे लेकिन लीडर कहां से लाएंगे, यह कोई नहीं सोच रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई एल्गोरिदम के इशारों पर नाच रहा है और एक जैसी भेड़चाल का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर इंस्टाग्राम पर कोई एक रील या ऑडियो क्लिप ट्रेंड कर गई, तो देश के लाखों लोग, चाहे वो स्टूडेंट हों, डॉक्टर हों या कोई और, अपनी गरिमा भूलकर उसी गाने पर एक जैसे स्टेप्स दोहराने लगते हैं। यह क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि डिजिटल गुलामी है। यहां तक कि हमारा घूमना-फिरना और सुकून भी अब फेयर आफ मिसिंग आउट और दूसरों को दिखाने की भेड़चाल से तय होता है। लोग किसी जगह को महसूस करने नहीं जाते, बल्कि सोशल मीडिया के बताए इंस्टा वारेथी या एस्थेटिक पॉइंट्स पर रील बनाने और फोटो खिंचाने जाते हैं। पहाड़ों पर लगने वाला मीलों लंबा ट्रैफिक जाम प्रकृति प्रेम का नहीं, बल्कि इसी नकलची संस्कृति का नतीजा है।अगर आप भीड़ से अलग कोई राय रखते हैं या स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, तो डिजिटल दुनिया आपको तुरंत अलग-अलग कर देगी, कैंसल या बॉयकॉट कर देने का डर दिखाने लगती है।

हिन्दी पत्रकारिता की दशा और दिशा

हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन के साथ हुई थी, जिसका अर्थ था 'समाचार सूर्य'। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छापी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे, इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया। 4 दिसम्बर 1826 से 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं।

(योगेश कुमार गोयल)

अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अनेक सफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैंकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता।

भारत में प्रेस ने लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी महत्ता सिद्ध की है, फिर चाहे भारत-पाक युद्ध हो या भारत-चीन लड़ाई अथवा अन्य कोई चुनौतीपूर्ण अवसर। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि हिन्दी पत्रकारिता का स्थान इसमें सर्वोपरि रहा है। हिन्दी भाषी समाचारपत्र हों अथवा पत्रिकाएं, उनका देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ सदैव विशेष जुड़ाव रहा है और इस दृष्टि से राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं विकास की दिशा में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्षों के इतिहास में समय के साथ पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य बदलते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद सुखद स्थिति यह है कि हिन्दी पत्रकारिता के पाठकों या दर्शकों की रूचि में कोई कमी नहीं आई। यह अलग बात है कि अंग्रेजी मीडिया और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों ने भले ही हिन्दी पत्रकारिता की उपेक्षा करते हुए सदैव उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें की हैं किन्तु वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ दशकों में हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी ताकत का बखूबी अहसास कराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यह हिन्दी पत्रकारिता की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि कुछ हिन्दी अखबारों ने अनेक संस्करणों के साथ प्रसार संख्या के मामले में कुछ अंग्रेजी अखबारों को भी पीछे छोड़ दिया है।

हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन के साथ हुई थी, जिसका अर्थ था 'समाचार सूर्य'। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छापी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे, इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया।

4 दिसम्बर 1826 से 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। 'उदन्त मार्तण्ड' के बाद अंग्रेजी शासनकाल में अनेक हिन्दी समाचारपत्र व पत्रिकाएं एक मिशन के रूप में निकलते गए किन्तु ब्रिटिश शासनकाल की ज्यादतियों के चलते उन्हें लंबे समय तक चलाते रहना बड़ा मुश्किल था, फिर भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने सराहनीय सफर तय किया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और हिन्दी पत्रकारिता भी मिशन न रहकर एक बड़ा व्यवसाय बन गई है किन्तु अच्छी बात यह है कि आज भी हिन्दी पाठक व दर्शक अपनी-अपनी पसंद के अखबारों व चैनलों के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हैं।

बहरहाल, घर बैठे-बैठे दुनिया की सैर कराने की बात हो या देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी हलचल से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों और हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों को जुटाकर अपने पाठकों या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की, व्यवसायीकरण के आरोपों या तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिन्दी पत्रकारिता भी यह काम बखूबी कर रही है और आमजन के भरोसे पर खरा उतरते हुए हिन्दी पत्रकारिता आज आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अनेक सफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैंकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता।

जहां तक राष्ट्रीय अखंडता में प्रेस की भूमिका और इसके दायित्वों का प्रश्न है तो प्रेस के कई प्रमुख दायित्व माने गए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि शामिल हैं। प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, ''प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं व विचारों को समझना और उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है।''

लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अखण्डता के संदर्भ में पत्रकारिता की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र के अन्य स्तंभों के मुकाबले प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्वभर में भारत की प्रतिष्ठा के जो तीन प्रमुख कारण माने गए हैं, वे हैं जागरूक मतदाता, स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र प्रेस। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी 'संसद' की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए ही कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने का अथवा उसे जागृत करने के लिए जन संचार का सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

वर्तमान में जहां देशभर में नैतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है और राजनीतिज्ञों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, वहीं हिन्दी पत्रकारिता भी इस नैतिक पतन का शिकार होने से नहीं बची है। फिर भी इतना संतोष तो किया ही जा सकता है कि इसने इसके बावजूद अधिकांश अवसरों पर सराहनीय भूमिका निभाई है। हालांकि आज के पूर्ण व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता को अव्यावसायिक बनाए रखने की बात करना बेमानी होगा क्योंकि इस पेशे से जुड़े लोगों को भी अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना अनिवार्य होता गया है लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में भी इसे एक उद्योग-धंधे के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के चलते पत्रकारिता के मानदंडों को ताक पर रखने की प्रवृति से तो हर हाल में बचना ही चाहिए।(लेखक 36 वर्षों से हिन्दी पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक-भारत की रक्षा क्रांति', 'प्रदूषण मुक्त सांसें' सहित कई चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

गौठान परिसर में कांग्रेस नेता ने किया सुसाइड, कुछ दिन पहले आया था जेल से छुटकर

रायपुर। शहर में पूर्व कांग्रेस नेता नवाज अली ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। संजय नगर स्थित गौठान परिसर में मंगलवार सुबह फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है। घटना की खबर इलाके में फैलते ही हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में कांग्रेस नेता जेल से बहार आया था। जानकारी के मुताबिक, कुछ महीने पहले कोदागांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें आरोप था कि नवाज अली की कार से पंचायत सचिव से ठोकर लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. तत्काल उसे स्थानियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता नवाज के खिलाफ एफ्आईआर दर्ज करते हुए जेल दाखिल किया था. हाल ही में नवाज अली जेल से बहार आया था, जिसके बाद आत्मघाती कदम उठाया. फ्लिहाल सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सुरक्षित नीचे उतारा और पंचनामा की कार्रवाई की. फ्लिहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मौज-मस्ती के लिए युवकों ने हार्वेस्टर चालक से की लूटपाट, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार

रायपुर। मोपका बायपास में हार्वेस्टर चालक से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटने वाले कम उम्र के लड़कों के गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कोनी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और नगदी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने घूमने-फिरने और अपने शौक पूरे करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीएसपी गगन कुमार (आईपीएस) के अनुसार, कबीरधाम जिले के ग्राम कामनबोड़ निवासी हरमेन्द्र साहू धान कटाई के काम से हार्वेस्टर मशीन लेकर बिलासपुर आए थे। 27 मई की रात ग्राम रमतला के पास उनकी मशीन खराब हो गई थी। मशीन सुधारने के बाद वे भोजन लेने मोटरसाइकिल से ढाबे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 28 मई की देर रात मोपका बायपास मोड़ के पास चार युवकों ने उनकी बाइक रोकने की कोशिश की। जब चालक नहीं रुका तो आरोपियों ने बाइक को लात मारकर गिरा दिया और हाथ, मुक्कों व बेल्ट से हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर चालक की जेब में रखे 10 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना की शिकायत मिलने पर कोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने मौज-मस्ती और निजी खर्चों के लिए लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफआगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्टील प्लांट में बायलर फटने से लगी आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं

रायपुर। आरंग स्थित मिवान (मोनेट) स्टील प्लांट में तड़के बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। प्लांट में बायलर फटने के बाद भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि धुएं और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दीं। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे के आसपास प्लांट परिसर में जोरदार धमाके के साथ बायलर फटा, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने प्लांट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठते देखा, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी शुरू की। फ्लिहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी।

मुंबई से फरार आरोपी रायपुर में गिरफ्तार, गीतांजलि एक्सप्रेस में जीआरपी ने दबोचा

रायपुर। छेड़छाड़ के मामले में मुंबई पुलिस को लंबे समय से तलाश रहे एक आरोपी को रायपुर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुंबई से हावड़ा जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी डोनी सरकार के खिलाफ मुंबई के कांदिवली पुलिस थाने में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत एफ्आईआर दर्ज है। मामले में आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश मुंबई पुलिस लगातार कर रही थी।

नैनो उर्वरकों के उपयोग से खेती बनेगी अधिक लाभकारी और टिकाऊ

खेती केवल आजीविका नहीं,हमारी संस्कृति और पहचान का आधार....

- ड्रोन से लेकर जैविक खेती तक, कृषि के हर नवाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- कम लागत, बेहतर उत्पादन और स्वस्थ मिट्टी का माध्यम है नैनो उर्वरक

रायपुर/ संवाददाता

आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित 'मुख्यमंत्री किसान संवाद' में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है। कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

नगरीय निकायों में 30 जून तक आयोजित किए जाएंगे स्वनिधि महोत्सव

रायपुर। संवाददाता

मेहनतकश स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के छह साल पूरे होने के मौके पर नगरीय निकायों में 30 जून तक लोक कल्याण मेलों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सवों का भी आयोजन किया जाएगा। इन दोनों आयोजनों के माध्यम से सड़क किनारे रोजी-रोटी कमाने वालों को अपने व्यवसाय को मजबूत करने सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाएगा। राज्य शासन ने स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेलों के आयोजन के लिए सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स), शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से स्वनिधि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में बैंकों के प्रतिनिधि छोटे व्यापारियों को ऋण स्वीकृति, वितरण, यूपीआई पंजीयन, क्यू-आर (क्क्क्) कोड सुविधा और डिजिटल भुगतान संबंधी सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराएंगे। स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

नैनो तकनीक से जिले के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव

- खेतों में नैनो यूरिया और डीएपी का सफल प्रयोग
- प्रगतिशील किसान शंकर लाल गुप्ता बने रोल मॉडल, कम लागत में बेहतर उत्पादन का दिया संदेश

रायपुर/ संवाददाता

सरगुजा जिले में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खेती की लागत कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने तथा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अब वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर के देवीगंज रोड निवासी एवं ग्राम बरकेला के प्रगतिशील किसान श्री शंकर लाल गुप्ता ने पिछले वर्ष अपने कृषि रकबे में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का सफल प्रयोग कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुप्ता ने बताया कि वे वर्षों से पारंपरिक दानेदार यूरिया एवं डीएपी का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उन्होंने नैनो उर्वरकों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से धान की फसल अधिक स्वस्थ, हरी-भरी तथा सुदृढ़ दिखाई दे रही है। फसल की वृद्धि बेहतर होने के साथ-साथ उत्पादन में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से परिवहन एवं भंडारण संबंधी समस्याओं में कमी आई है।

मछली पालन ने ग्रामीण महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भ

वन विभाग में विभागीय जांच की सुस्ती पर एक्शन

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा-देरी पर होगी कार्रवाई

- वन मंत्री ने कहा-तीन माह में जांच प्रकरणों को निराकृत करें

रायपुर। संवाददाता

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग में वर्षों से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों को आगामी तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद यदि पुराने प्रकरण असामान्य अथवा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संबंधित जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। वन मंत्री ने कहा कि विभागीय जांच मामलों में अनावश्यक देरी न केवल प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है, बल्कि इससे कर्मचारियों को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक एवं सेवा संबंधी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में निर्णयहीनता और अनावश्यक विलंब के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कश्यप ने कहा कि कई मामलों में विभागीय जांच प्रस्ताव 4-5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि कुछ प्रकरण संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भेजे जाते हैं।

तहसीलदारों की हड़ताल पर बोले राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा- सचिव स्तरीय चर्चा से जल्द निकलेगा रास्ता

रायपुर। सीतापुर की घटना के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के आंदोलन को लेकर सरकार और राजस्व अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के सरकारी निवास पर कनिष्ठ प्रशासनिक संघ और राजस्व विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान तहसीलदार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और आपत्तियों को सरकार के सामने रखा। वहीं, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। बता दें कि सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा नायब तहसीलदार तुषार मानिक की कथित पिटाई के बाद, राज्य के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं।

प्रगतिशील किसान खानेंद्र की प्रेरणादायक कहानी...

- फसल उत्पादन में नैनो डीएपी एवं यूरिया के उपयोग से जमीन की बनी रहेगी उर्वरकता

रायपुर। संवाददाता

नारायणपुर के ग्राम केरलापाल के निवासी खानेंद्र कुमेटी एक मेहनती और प्रगतिशील किसान हैं। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ वर्ष पहले तक वे पारंपरिक खेती करते थे, जिससे उन्हें बहुत कम लाभ मिलता था। खेती की लागत बढ़ रही थी और उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो रहा था। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पा रही थी। खानेंद्र कुमेटी ने हार मानने के बजाय नई तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उन्नत बीजों का उपयोग शुरू किया, खेतों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाया तथा सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया। इससे उनकी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ सब्जियों और फलदार पौधों की खेती भी शुरू की। फसल विविधीकरण के कारण उनकी आय के स्रोत बढ़ गए। उन्होंने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई, जिससे पानी की बचत हुई।

सुशासन तिहार : मौके पर ही दूर हो रही हैं जनता की तकलीफे

विकास कार्यों में नही होगी कोई कमी-राजस्व मंत्री टंकराम

- छेरकापुर में मंत्री टंकराम वर्मा ने दी 55 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निराकरण के लिए 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम छेरकापुर में एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर के दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 55 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुंचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान,समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और

गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के विकास हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का जमीनी स्तर पर समाधान करना है। 'विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी' के तहत राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अभियानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 'मोर गाँव मोर पानी अभियान 2.0' के तहत जल संचयन दीदियों और ग्राम पंचायतों के साझा प्रयासों से महज ढाई महीने के भीतर ढाई लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जारी 'हम होंगे कामयाब 2.0' वेब पोर्टल की भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल रही हैं। इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और बड़ी संख्या में हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया गया।

संक्षिप्त समाचार

राजिम पुलिस ने 13.775 किलो गांजा किया जब्त 5 आरोपी पकड़ाए

रायपुर। राजिम पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार से 13.775 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोरा तालाब के पास घेराबंदी कर यह कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर कार से करीब 6.77 लाख रुपये मूल्य का गांजा मिला। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट डिजायर कार और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 14.12 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने धमतरी और ओडिशा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं मामले में 2 विधि से संघर्षरत बालकों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है तथा मामले की आगे की जांच जारी है।

किसान ने किया सुसाइड मामले में पड़ोसी गिरफ्तार

रायपुर। जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम फरहदा में घर और जमीन खाली कराने के लिए लगातार दबाव, गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकियों से परेशान होकर जहर खाने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफआत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धारा जोड़ते हुए कार्रवाई की है। डीएसपी डीआर टंडन ने बताया कि ग्राम फरहदा बजरंग चौक निवासी परमेश्वरी पटेल ने शुक्रवार को सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वे और उनका परिवार सरकारी जमीन पर बने मकान में रह रहे हैं। पड़ोस में रहने वाला बलराम यादव एक बुजुर्ग महिला को साथ लेकर उनके घर पहुंचा और जमीन को उसका बताते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने घर में घुसकर अश्लील गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना से आहत परमेश्वरी के पति कनक पटेल ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उन्हें सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी लंबे समय से कनक पटेल और उनके परिवार को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मौत के बाद मामले में बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना) जोड़ी गई। अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई। घटना के बाद फरार हुए आरोपी बलराम यादव को सीपत पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने गनियारी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पीएम स्वनिधि से बदली सोहन की जिंदगी

रायपुर। राजधानी रायपुर के ब्रम्हदेईपारा, खमतराई निवासी फल व्यवसायी सोहन लाल साहू के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आर्थिक संकट के दौर में बड़ी मददगार साबित हुई। कोरोना संक्रमण काल में व्यवसाय प्रभावित होने से उनके परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बन गया था। सोहन लाल साहू ने बताया कि इसी दौरान रायपुर नगर पालिक निगम के माध्यम से उनका आवेदन पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत हुआ और उन्हें प्रथम चरण में 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने अपने फल व्यवसाय को दोबारा शुरू किया। समय पर ऋण चुकाने पर उन्हें दूसरे चरण में 20 हजार रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया। लगातार समय पर ऋण अदायगी और बेहतर रिकॉर्ड के चलते उन्हें तीसरे चरण में 50 हजार रुपये का ऋण भी स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहायता से उन्होंने एक और ठेला खरीदा और वर्तमान में दो ठेलों के माध्यम से फल व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। सोहन लाल साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कठिन समय में उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। उन्होंने इस योजना तथा रायपुर नगर पालिक निगम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रही है और उन्हें आगे बढ़ने का नया अवसर प्रदान कर रही है।

नकाबपोश चोरों का मेडिकल दुकानों पर धावा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

रायपुर। जिले के करहीभदर गांव में रविवार रात दो नकाबपोश चोरों ने मेडिकल दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के करहीभदर गांव स्थित दो मेडिकल दुकानों में देर रात चोरी हुई। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर प्रवेश किया ।

159 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यो की दी सौगात

कार्यालयों के चक्कर नहीं,अब गांव में ही समस्याओं का निराकरण-साव....

■ उपमुख्यमंत्री श्री साव के आतिथ्य में डोंगा नाला में जनसमस्या निवारण शिविर का हुआ आयोजन

रायपुर/ संवाददाता

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज कोरबा जिले के विकासखण्ड पाली के ग्राम डोंगानाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने शिविर में 159 करोड़ 63 लाख 14 हजार की राशि के 18 विकास कार्यो की सौगात दी। जिसके अंतर्गत 153 करोड़ 66 लाख 61 हजार के कुल 8 कार्यो का भूमिपूजन, 5 करोड़ 96 लाख 53 हजार के 10 विकास कार्यो का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जिलेवासियों को विकास कार्यो के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक पाली तनाखार श्री तुलेश्वर मरकाम, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया रूपेश कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पाली श्री अजय जायसवाल, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दुगनी गति से पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब महिलाएं लखपति दीदी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिला सहित पाली तानाखार क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पाली तानाखार विधानसभा में सभी प्रकार के निर्माण व अन्य प्रशासनिक काम तेजी से हो रहा है। अनेक विकास कार्यो के लिए डीएमएफ से पर्याप्त राशि क्षेत्र को मिल रहा है। श्री साव ने कहा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की जा रही है।

बच्चों एवं वृद्धों के मुख्य पोषण का आहार दूध.....

रायपुर/ संवाददाता

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। चिकित्सकों की राय में बच्चों एवं वयोवृद्धों के लिए कैल्सियम की कमी शरीर में एवं हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्य आधार दूध ही है। एक समय जब भारत में दुग्ध उत्पादन काफी कम था। गुजरात के आनंद डेयरी ने सबसे पहले अमूल उत्पाद के जरिये देश भर में सहकारी सेक्टर में दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर दुग्ध क्रांति की। इसके बाद दूध की कमी पूरे देश से खत्म हो गई। आज छग में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से देवभोग न केवल दूध बल्कि दूध से बने उत्पाद खोवा, श्रीखंड, पेड़ा, पनीर सहित अनेक दुग्ध सामाग्री की बिक्री कर रहा है। छग शासन के सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव गणेश शंकर मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसानों को विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर नमन करते हुए बधाई दी है। छोटों से लेकर बड़ों तक में दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। बीमारी चाही जैसी भी हो डाक्टर आमतौर पर मरीजों को फल के साथ ही दूध सेवन करने की सलाह देते है। आज दूग्ध उत्पादन की दिशा में छग आत्मनिर्भर हो चुका है। पशुआहार में मूल्यों की वृद्धि के चलते रायपुर निजी दूध डेयरियों के माध्यम से दूध इन दिनों गाय का 70 रुपये एवं भैंस का 80 लीटर बिक रहा है। जबकि देवभोग गोरस एक लीटर दूध 55 से 60 रुपये लीटर के बीच बेचा जा रहा है। खोवा प्रति किलो 370 रुपये देवभोग पार्लर वाले बेच रहे हैं। जबकि निजी होटल संचालक व 400 रुपये किलो अधिक की दर पर बेच रहे हैं। सरकारी दुग्ध पार्लरों के जरिए बनने वाली मिठाईयों के दाम अभी भी कम है जबकि मिठाईयों की दुकान में बड़ी दुकानों से लेकर छोटी दुकानों तक में छह सौ रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक की मिठाई राजधानी में बिक रही है। सहकारी क्षेत्र के माध्यम से जहां राज्य शासन ने दुग्ध उत्पादकों को दूध उचित मूल्य पर लेकर लाभान्वित किया है वहीं सरकारी दूध पार्लर वाले भी उचित कमीशन पर दूध एवं अन्य सामाग्रियों की बिक्री कर लाभान्वित हो रहे है।

मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर महिला को बनाया शिकार

■ नशीला भोजन खिलाकर लाखों के जेवर लेकर फरार हुए आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। संवाददाता

राजधानी रायपुर में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिला से दोस्ती कर उसे ठगी और चोरी का शिकार बनाने वाले दो शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला को जन्मदिन पार्टी के बहाने घर बुलाया, नशीला पदार्थ मिलाकर भोजन खिलाया और बेहोश होने पर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार खम्हारडीह निवासी एक महिला की पहचान करीब चार माह पहले जीवनसाथी डॉट कॉम के माध्यम से अभिनव सिंह नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। 15 मई 2026 को अभिनव सिंह ने महिला को जन्मदिन मनाने के बहाने उसके घर पहुंचने की जानकारी दी। दोपहर में वह महिला के घर पहुंचा और साथ में भोजन किया। आरोप है कि भोजन के दौरान अभिनव सिंह ने चिकन को ठीक से नहीं पकने की बात कहकर दोबारा तैयार किया और उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को खिला दिया। भोजन के कुछ देर बाद महिला बेहोश हो गई। अगले दिन होश आने पर उसने देखा कि उसके गले की सोने की चेन, अंगूठियां तथा आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब हैं। वहीं आरोपी भी घर से फरार हो चुका था। महिला की शिकायत पर खम्हारडीह थाना में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) और पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह की संयुक्त टीम गठित की गई।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने जन्मदिवस पर किया सुंदर कांड पाठ, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

सुशासन तिहारके अंतर्गत चार जिलों की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास,धान उठाव और कृषि तैयारियों पर विशेष जोर दिया

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अमला सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयासों के साथ कार्य करे, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और सुशासन की भावना जमीन पर दिखाई दे। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मंगलवार शाम कांकेर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को पक्के आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की प्रक्रिया तेज करने तथा स्थानीय स्तर पर धान मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

भनपुरी की प्यास बुझाने निगम अलर्ट, टैंकरों से टेल एंड क्षेत्रों में राहत

रायपुर। शहर के कई हिस्सों में जलस्तर गिरने से पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है, लेकिन भनपुरी क्षेत्र में लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया है। रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक-1 अंतर्गत बंजारी माता वार्ड में स्थित भनपुरी की 2000 किलोलीटर क्षमता वाली पुरानी पानी टंकी को पूरी क्षमता तक भरा जा रहा है, जबकि 3200 किलोलीटर क्षमता वाली नई टंकी में फिलहाल 80 से 85 प्रतिशत तक ही जलभराव हो पा रहा है। निगम प्रशासन के अनुसार ग्रीष्मकाल में अधिकांश बोरवेलों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण पूरे शहर की जल व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके साथ ही टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त जलापूर्ति और वाटर बैलेंसिंग की तकनीकी चुनौतियों के चलते अंतिम छोर पर स्थित नई भनपुरी टंकी अपेक्षाकृत कम भर पा रही है। इधर बंजारी माता वार्ड के रामेश्वर नगर, बुनियाद नगर, कमल चौक और केबिनपारा जैसे टेल एंड क्षेत्रों में पानी का दबाव कम होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है।

बागवानी फसलों से किसानों की आय में हो रही समृद्धि....

■ उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों मिल रहा तकनीकी मार्गदर्शन

रायपुर। संवाददाता

जिले में उद्यानिकी (बागवानी) फसलों की खेती किसानों के लिए आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ-साथ अब बड़ी संख्या में किसान बागवानी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले में सैकड़ों किसान सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर बेहतर लाभ अर्जित कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि अंतर्वर्ती एवं विविध फसलों की खेती के परिणाम पहले भी उत्साहजनक रहे हैं और वर्तमान में भी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि लगातार एक ही प्रकार की फसल लेने से उत्पादन लागत बढने, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने तथा मौसम संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत उद्यानिकी फसलों से किसानों को कम समय में बेहतर आमदनी प्राप्त हो रही है। अधिकारियों के अनुसार कोरबा जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है। किसानों के अनुभव भी इस दिशा में सकारात्मक रहे हैं। पहले जहां अधिकांश किसान धान और अन्य पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे।

खरीफ सीजन की तैयारियां तेज

किसानों को मांग अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा खाद और बीज

■ जिले में 24 हजार टन से अधिक उर्वरक का भंडारण, सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर वितरण

रायपुर/ संवाददाता

जिला रायगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले जिले के किसान आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। खेतों की जुताई, बुआई की तैयारी और कृषि आदानों की व्यवस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं पात्र किसानों को नगद ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। कलेक्टर द्वारा इसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खाद की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफविपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले में उर्वरकों के भंडारण और वितरण की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से संचालित की जा रही है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा

रही है, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले में अब तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का 24 हजार 138 टन से अधिक भंडारण किया जा चुका है। इनमें सहकारी संस्थाओं में 15 हजार 789 टन तथा निजी क्षेत्र में 8 हजार 348 टन उर्वरक उपलब्ध है। कृषि विभाग के अनुसार सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरकों की पहुंच और वितरण व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 48 प्रतिशत तथा गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 52 प्रतिशत खाद का भंडारण किया जा चुका है। वहीं इस वर्ष उपलब्ध कराए गए भंडारण के विरुद्ध लगभग 46 प्रतिशत उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खाद की आपूर्ति एवं भंडारण की प्रक्रिया चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा जिले में गठित निगरानी दलों, उर्वरक निरीक्षकों तथा मैदानी अमले के माध्यम से सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को उनके कृषि रकबे एवं आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

बौद्ध चैत्यगृह भोंगापाल से प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री एवं शांति का संदेश चारों ओर फैलेगा

बौद्ध चैत्यगृह भोंगापाल में प्रदेश स्तरीय बुद्ध जयंती एवं सम्मान समारोह आयोजित

भोंगापाल/नारायणपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग में कोण्डागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित भोंगापाल में छठी शताब्दी का प्राचीन बौद्ध चैत्यगृह और बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। यह स्थान आदिवासी परंपराओं एवं मान्यताओं के साथ बौद्ध धम्म दर्शन का अनूठा संगम है। भोंगापाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुद्ध जयंती समारोह का शुभारंभ प्राचीन बौद्ध चैत्यगृह में विशाल बौद्ध प्रतिमा के सम्मुख केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ टेकाम, बौद्ध समाज के संरक्षक महादेव कावरे, दिलीप वासनीकर, डॉ कृष्णमूर्ति कांबले, आलोक देव एवं छत्तीसगढ़ बौद्ध समाज के प्रदेश अध्यक्ष अनिल खोबरागड़े, भोंगापाल के सरपंच रामसाय नाग, जयंत वासनीकर एवं फूल सिंह कोर्राम के साथ विभिन्न जिलों से आये बौद्ध समाज के प्रमुखों द्वारा मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाकर सामूहिक रूप से बुद्ध वंदना कर त्रिशरण पंचशील का पाठ किया गया। इसके पश्चात डॉ.कृष्णमूर्ति कांबले की अगुवाई में राज्य स्तरीय भोंगापाल बुद्ध महोत्सव कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुध्ददेव संरक्षण समिति के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों एंव विभिन्न जिलों से आये बौद्ध समाज के विशिष्टजनो को मेडल, बौद्ध स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ टेकाम ने अपने संबोधन में कहा की हाईवे रोड से भोंगापाल कैसे पहुंचा जा सकता है यह बताने साइन बोर्ड लगाने एवं सुगम आवागमन के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीणों की मांगों के अनुरूप भोंगापाल में बुद्ध के नाम पर महाविद्यालय और उच्च स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है जिसका लाभ तीनों जिलों के लोग ले सके। आयुक्त एवं बौद्ध समाज के संरक्षक महादेव कांवरे ने बौद्ध चैत्यगृह का संरक्षण, संवर्धन करने एवं यहां आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को विकसित करने पर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व कमिश्नर दिलीप वासनीकर ने बस्तर कमिश्नर के रूप में इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि सामाजिक एकजुटता के साथ इस क्षेत्र में लगातार बौद्ध धम्म के आयोजन किए जाने चाहिए। भोंगापाल बुद्ध जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल खोबरागड़े ने कहा कि भोंगापाल बौद्ध चैत्यगृह से तथागत गौतम बुद्ध के प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री एवं शांति का संदेश चारों ओर फैलेगा। भोंगापाल क्षेत्र के आदिवासी समाज एवं सर्व समाज के सहयोग से हम लगातार बौद्ध चैत्यगृह में कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। उन्होंने बुद्ध जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए ग्राम वासियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बौद्ध समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदेश स्तरीय बुद्ध जयंती समारोह एवं सम्मेलन में उपस्थित बौद्ध समाज ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन 6 वीं शताब्दी में निर्मित छत्तीसगढ़ के एकमात्र बौद्ध चैत्यगृह एवं विशाल बौद्ध प्रतिमा का संरक्षण, संवर्धन करें। बौद्ध धम्म दर्शन को ध्यान में रखते हुए भोंगापाल में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पार्क की स्थापना की जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बौद्ध चैत्यगृह भोंगापाल को प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।भोंगापाल में सर्वसुविधायुक्त बौद्ध विहार एवं ध्यान/ विपश्यना केन्द्र का निर्माण किया जाए। शासन द्वारा भोंगापाल में बौद्ध कालीन संस्कृति एवं सभ्यता को ध्यान में रखते हुए व्यापक क्षेत्र में उत्खनन किया जाना चाहिए। जिला मुख्यालय कोंडागांव, नारायणपुर एवं कांकेर से भोंगापाल बौद्ध चैत्यगृह जाने वाले मार्ग पर साइन बोर्ड लगाकर अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाय।

विभागीय अधिकारियों ने किया विस्तृत निरीक्षण, पीएमजीएसवाए के प्रमुख अभियंता के.के. कटारे ने की सड़कों की गुणवत्ता की जांच

बीजापुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले के बीजापुर में पीएमजीएसवाए योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं प्रगतिरत सड़को की गुणवत्ता की व्यापक जांच की गई। प्रमुख अभियंता के.के कटारे, अधीक्षण अभियंता मनोज रात्रे सहित विभागीय अमले ने विभिन्न निर्माण स्थलों पर पहुंचकर सड़को का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी मापदंडों, सड़क की मोटाई, सतह की मजबूती जल निकासी व्यवस्था तथा सुरक्षा मानको की विस्तार से जांच की गई है। भोपालपटनम विकासखं में उल्लूर से केरपे, लंबाई 90 कि.मी. सड़क की भी विभागीय टीम ने गुणवत्ता जांच की। निरीक्षण के दौरान सड़कों की सतह, मजबूती एवं तकनीकी मानकों के अनुरुप कार्य नही कराये जाने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदार अंकित गुप्ता को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जाना संभव है साथ ही सड़क के बगल से खाई नूमा मिटटी खोद कर अर्थवर्क कार्य करने पर एवं मनमर्जी ढंग से किसी भी स्थान पर पुलिया बनायें जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा ठेकेदार अंकित गुप्ता को निर्देशित किया गया कि सभी पुलियों को तोड़कर विभागीय अभियंताओ के निर्देशानुसार पुनः कार्य किया जावे एवं सड़क के बगल से मिटटी खोदे जाने के कारण सड़क में कटाव होने कि आंशका के कारण उसे भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पालनार से रेगडगटटा लंबाई 5 कि.मी. एवं भैरमगढ़ बीजापुर रोड़ 20 कि.मी. से बडेतुंगली ठेकेदार दंगल बिल्डर्स को कार्यो को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। एल.26 बोगामगुडा से गुमरा ठेकेदार हरबीर सिंह बदेशा गुणवत्तापूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही स्थल का विभागीय एवं ठेकेदार के तकनीकी अमलों के साथ पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से विशेष रुप से अति पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, जिससे ग्रामीणों को शिक्षात्र स्वास्थ्य सेवाओं, बाजार एवं रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होनें यह भ कहा कि ग्रामीण सड़कें क्षेत्रीय विकास की आधारशीला होती हैं और इनके माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलती है। प्रमुख अभियंता के.के कटारे द्वारा ठेकेदारों एवं विभागीय अभियंताओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्वता का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे बीजापुर जिले में नक्सल उलमूलन के उपरांत जिले के विकास कार्यों में तेजी आये एवं ग्रामीण जनता सीधे संपर्क मार्गो से जुड़ सकें।

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने मुख्यमंत्री को सुनाया 'बदलते बस्तर' का गीत, प्रतिभा को मिली सराहना

नारायणपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गारपा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अबूझमाड़ के ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान जिले के नितारा (नारायणपुर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड रूरल आर्ट) से जुड़े कलाकारों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कला और प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने बदलते बस्तर विषय पर आधारित गीत एवं नाट्य प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के माध्यम से यह दर्शाया गया कि किस प्रकार शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक प्रयासों से कभी पिछड़े और विकास से दूर रहे गांव आज मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। विशेष बात यह रही कि प्रस्तुति देने वाले कलाकारों में आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा संचालित निताारा के 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें संगीत, नृत्य, अभिनय एवं अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन युवाओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नई दिशा में बढ़ते जीवन का संदेश दिया। आत्मसमर्पित युवाओं की कला, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव की भावना को देखकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर के युवाओं में अपार प्रतिभा है और उन्हें अवसर एवं मार्गदर्शन प्रदान कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना शासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

मानसून 2026 के मद्देनजर जिला स्तरीय बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष हुआ सक्रिय

दंतेवाड़ा। आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, आंधी-तूफान एवं अन्य आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय दंतेवाड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मानसून वर्ष 2026 के दौरान बाढ़, अतिवृष्टि एवं आंधी-तूफान से होने वाली जन-धन हानि, फसल क्षति, मकान क्षति तथा अन्य प्राकृतिक आपदा संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने, उसका संकलन करने और राहत कार्यों के समन्वय हेतु जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के नियंत्रण कक्ष क्रमांक-137 में आगामी आदेश तक जिला स्तरीय बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम पाली प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा तृतीय पाली रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक संचालित होगी। प्रथम पाली में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग दंतेवाड़ा के अधीन कार्यरत सहायक ग्रेड-03 हर्षित गौतम को तहसीलों से प्राप्त होने वाली जानकारी का संकलन कर निर्धारित प्रारूप (एनेक्सर-01) में दैनिक प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 नरेन्द्र टंडन को प्रतिदिन होने वाली क्षति की जानकारी का पंजी संधारण एवं अभिलेखीकरण करने का दायित्व सौंपा गया है। इनके सहयोग के लिए श्रम विभाग के भृत्य नागेन्द्र प्रसाद पटेल को तैनात किया गया है। दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित होने वाली द्वितीय पाली में उप संचालक उद्यान विभाग दंतेवाड़ा के ग्रेड-03 कर्मचारी रामजी नाग को प्रथम पाली में किए गए समस्त कार्यों का प्रभार लेकर नियंत्रण कक्ष संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। शासकीय हाई स्कूल कांवड़गांव के सहायक ग्रेड-03 भगत राम ठाकुर को उनकी ड्यूटी अवधि में प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं एवं जानकारियों को तत्काल जिला नियंत्रण अधिकारी तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भृत्य पलाश जोध भी नियंत्रण कक्ष में सेवाएं देंगे। रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक संचालित तृतीय पाली में उप वनमंडल कार्यालय गीदम के वायरलेस ऑपरेटर शम्भूनाथ झा तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेटापाल के सहायक ग्रेड-03 बसंत यदु की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें द्वितीय पाली में सौंपे गए सभी कार्यों का प्रभार लेकर नियंत्रण कक्ष संचालन, सूचनाओं का संकलन एवं जिला नियंत्रण अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त राहत शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का भी निष्पादन किया जाएगा।

नारायणपुर में खनिजों के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 5 हाइवा वाहन जब्त

नारायणपुर। खनिज जांच दल द्वारा गत 23 मई को जिले में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान साधारण पत्थर (गिट्टी) एवं रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 5 हाइवा वाहनों को जब्त कर कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला नारायणपुर में सुरक्षित रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जब्त वाहनों में रेत एवं साधारण पत्थर (गिट्टी) का परिवहन बिना वैध अभिवहन पास के किया जा रहा था। जब्त किए गए वाहनों में नारायणपुर, रायपुर, राजनांदगांव एवं कोंडागांव जिले के वाहन शामिल हैं। इनमें दो वाहन रेत परिवहन तथा तीन वाहन साधारण पत्थर (गिट्टी) के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए। खनिज विभाग के अनुसार सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 (5) तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। इसके तहत खनिज अमले द्वारा लगातार जांच एवं निगरानी अभियान जारी रखा जाएगा, ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

ग्राम पंचायत सुरनार में क्लस्टर स्तरीय शिविर आयोजित, 221 आवेदन प्राप्त

दंतेवाड़ा। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत सुरनार में क्लस्टर स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत धनीकरका, दुवालीकरका, बुरदीकरका, नड़ियापदर, सुरनार, गाटम एवं बड़ेलखापाल के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चैतराम अटामी शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद पंचायत कटेकल्याण के उपाध्यक्ष भीमसेन मंडावी सहित जनपद सदस्य, सरपंच, पंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दो दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण के रूप में छड़ी एवं व्हीलचेयर वितरित की गई। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तीन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा चार शिशुओं के अन्नप्राशन संस्कार की रस्म संपन्न कराई गई। शिविर में कुल 14 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजन की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। इस दौरान कुल 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 216 मांग संबंधी तथा 5 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। शिविर में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा विभिन्न सुविधाओं एवं विकास कार्यों से संबंधित मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। आयोजन के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ तथा समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

भानुप्रतापपुर में निजी अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद गरमाई राजनीति

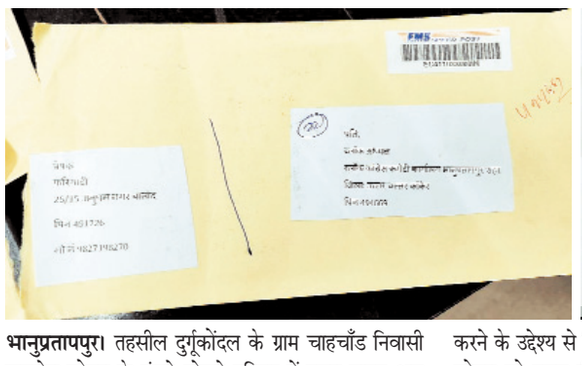

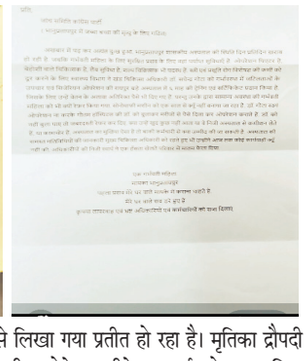

भानुप्रतापपुर। तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम चाहचाँड निवासी कमलेश कोमरा के हंसते-खेलते परिवार में पसरा मातम अब प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बीते दिनों कमलेश की 31 वर्षीय गर्भवती पत्नी द्रौपदी कोमरा और उनके नवजात बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस संवेदनशील मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष को बालोद से स्पीड पोस्ट के जरिए एक शिकायती पत्र मिला है, जिसकी सत्यता और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह पत्र किसी बड़ी साजिश या आपसी रंजिश के तहत आदिवासी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को जानबूझकर टारगेट करने के उद्देश्य से लिखा गया प्रतीत हो रहा है। मृतिका द्रौपदी कोमरा को प्रसव पीड़ा होने पर बीते 15 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर में भर्ती कराया गया था। 17 मई को सोनोग्राफी और अन्य जांचों में पता चला कि गर्भ में 'वाटर लेवल' (एमनियोटिक फ्लूइड) बेहद कम है, जिससे सामान्य प्रसव असंभव था और जच्चा-बच्चा दोनों की जान को गंभीर खतरा था। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने बेहतर इलाज की उम्मीद में मरीज को भानुप्रतापपुर के ही निजी 'गौतम हॉस्पिटल' में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि गौतम हॉस्पिटल में उन्हें 5 घंटे तक इंतजार कराया गया। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने बार-बार सिजेरियन (ऑपरेशन) करने की गुहार लगाई, लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी और जबरन नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करते रहे। इस लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि माँ और बच्चे दोनों की तड़पकर मौत हो गई।

पीएम न होना खड़ा करता है बड़ा सवाल

इतनी बड़ी घटना और कथित लापरवाही के बाद भी जच्चा-बच्चा दोनों के शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? कानूनन और प्रशासनिक तौर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, यह आज भी अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

बालोद से आए पत्र ने खोला संशय का पिटारा: फर्जी होने की आशंका

इस दुखद घटना के बीच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बालोद से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में पूरी घटना का ठीकरा निजी गौतम हॉस्पिटल पर फोड़ने के बजाय, सिर्फ और सिर्फ शासकीय अस्पताल और वहां के बीएमओ डॉ. सचेन्द्र गोटा पर मढ़ा गया है। पत्र में लिखा गया है कि डॉ. गोटा प्रशिक्षित होने के बाद भी खुद ऑपरेशन न करके निजी अस्पताल से कमीशनखोरी करते हैं।

लेकिन इस पत्र की कड़ियों को जोड़ने पर इसके 'फर्जी' और 'प्रायोजित' होने की बू आ रही

लापरवाही निजी अस्पताल की, निशाना सरकारी डॉक्टर पर: घटना पूरी तरह से निजी गौतम हॉस्पिटल में घटी, जहां डिलीवरी के दौरान दोनों की मौत हुई। लेकिन पत्र में गौतम हॉस्पिटल की लापरवाही का कोई जिक्र न करते हुए, केवल आदिवासी बीएमओ को निशाना बनाया गया है।

भानुप्रतापपुर का मायका, तो बालोद से पोस्ट क्यों?

पत्र लिखने वाले ने खुद को महिला बताते हुए लिखा है कि उसका मायका भानुप्रतापपुर में है और वह वहीं डिलीवरी कराना चाहती थी। यदि शिकायतकर्ता वर्तमान में भानुप्रतापपुर में ही है, तो पत्र भानुप्रतापपुर से पोस्ट न होकर बालोद से क्यों भेजा गया?

अधूरी जानकारी और बंद मोबाइल नंबर

यदि शिकायत वास्तविक और दमदारी से की गई होती, तो शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी पहचान उजागर की होती। पत्र में जो मोबाइल नंबर अंकित किया गया है, वह लगातार बंद आ रहा है। पत्र में पीड़ित परिवार के साथ घटे वास्तविक घटनाक्रम का कोई प्रामाणिक विवरण नहीं है, जिससे साफ होता है कि यह केवल शासकीय डॉक्टर की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से रची गई एक साजिश है।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले में जहां एक ओर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक आदिवासी अधिकारी को सोची-समझी रणनीति के तहत घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास पहुंचे इस संदिग्ध पत्र पर संगठन और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या इस फर्जी पत्र की जांच होगी या फिर असली दोषियों निजी अस्पताल को बचाने के लिए सरकारी तंत्र को बलि का बकरा बनाया जाएगा? यह आने वाला समय ही बताएगा।

अंतागढ़ में 36 घंटे से चक्काजाम: ब्लॉक मुख्यालय की मांग को लेकर 68 गांवों के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे-5 किया ठप

भानुप्रतापपुर। कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय को वापस उसके मूल स्थान पर संचालित करने की मांग को लेकर कोयलीबेड़ा अंचल के ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। अंतागढ़ में पिछले 30 घंटों से स्टेट हाईवे क्रमांक 5 पूरी तरह से ठप है। 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांवों से आए हजारों ग्रामीणों ने कुहचे चौक और इमलीपदर चौक पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम कर दिया है, जिससे अंतागढ़ शहर का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आंदोलन के दूसरे दिन भी स्थिति जस की तस तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय 'लिंक कार्यालय' के नाम से पखांजूर में चलाया जा रहा है। इसके कारण छोटे-छोटे प्रशासनिक और दस्तावेजी कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को मीलों दूर पखांजूर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी बर्बादी होती है।

चारों तरफ से घिरा अंतागढ़, पुलिस की गाड़ियां भी रोकी गईं

शुरुआत में ग्रामीणों ने केवल कुहचे चौक पर मोर्चा संभाला था, लेकिन आंदोलन उग्र होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इमलीपदर चौक को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके चलते पूरा अंतागढ़ शहर एक तरह से किले में तब्दील हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि न तो कोई व्यक्ति शहर में प्रवेश कर पा रहा है और न ही बाहर जा पा रहा है। आक्रोशित भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस की गाड़ियों को भी शहर के भीतर दाखिल होने से रोक दिया है।

साप्ताहिक बाजार प्रभावित, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें

बीते दिन अंतागढ़ का साप्ताहिक बाजार होने के कारण अंचल के दूर-दराज के ग्रामीण अपनी जरूरत का सामान खरीदने पहुंचे थे, लेकिन चक्काजाम के चलते पूरा बाजार और आम जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। स्टेट हाईवे बंद होने की वजह से सड़क के दोनों ओर मालवाहक वाहनों और यात्री बसों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे राहगीर और स्थानीय लोग परेशान हैं।

ज्ञापन में शामिल प्रमुख 10 सूत्रीय मांगें

स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट विद्यालय को ब्लॉक मुख्यालय के नाम से पखांजूर में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे वापस कोयलीबेड़ा क्षेत्र में ही रखा जाए। क्षेत्र में 'जिला सहकारी बैंक' की शाखा खोली जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मूलभूत मांगों को पूरा किया जाए, नया सोलर सिस्टम लगाया जाए, महिला डॉक्टर की पदस्थापना हो, रिक्त पदों को भरा जाए तथा नए भवन की स्वीकृति दी जाए। क्षेत्र में खाद और बीज की समस्या का स्थाई निराकरण किया जाए। जर्जर हो चुके स्कूलों और आश्रमों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। इसी चालू सत्र से क्षेत्र में एक नया कॉलेज खोला जाए। ब्लॉक मुख्यालय के समस्त कार्यालयों का संचालन पूर्ण रूप से कोयलीबेड़ा से ही किया जाए। जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि प्रभावित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत खर्च की जाए। कोयलीबेड़ा से अंतागढ़ मार्ग का तत्काल डामरीकरण कार्य कराया जाए। राजस्व प्रकरणों के सरलीकरण हेतु कोयलीबेड़ा तहसील को अनुभाग अंतागढ़ में जोड़ा जाए।

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फूटा गुस्सा, फूंका पुतला

मुख्यालय स्थानांतरण के मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक विक्रम उसेंडी और कांकेर के सांसद भोजराज नाग पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उनके पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी की।

राशन-पानी साथ लेकर सड़क पर ही गुजारी रात

यह आंदोलन लंबे खिंचने के आसार हैं क्योंकि ग्रामीण पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वे अपने साथ पर्याप्त राशन, पानी और खाना पकाने के बर्तन लेकर आए हैं। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे हजारों ग्रामीणों ने रात स्टेट हाईवे पर ही गुजारी और वहीं सामूहिक रूप से भोजन पकाया। उनका साफ कहना है कि जब तक ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे।

मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, दिया वार्ता का आश्वासन

इस बड़े आंदोलन की गूंज राजधानी और बस्तर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तक पहुंच चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा, सरकार ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। जल्द ही आंदोलनकारियों से सीधे बातचीत कर इस संवेदनशील मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र में 'समन्वय-2026' का शुभारंभ, 10.2 एमटीपीए विस्तार परियोजना के लिए वेंडर मीट सम्मेलन आयोजित

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 6.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 10.2 एमटीपीए करने की प्रस्तावित विस्तार परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बीएसपी के परियोजना विभाग द्वारा 03 जून 2026 को भिलाई निवास में दो दिवसीय विक्रेता सहयोग सम्मेलन (वेंडर मीट) 'समन्वय-2026' का शुभारंभ किया गया। ÷भविष्य के विस्तार हेतु सहभागिता का सुदृढ़ निर्माण÷ विषय पर आधारित यह सम्मेलन प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, ईपीसी एजेंसियों, सलाहकारों, उपकरण निर्माताओं, सेवा भागीदारों तथा परियोजना हितधारकों के बीच समन्वित सहयोग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक प्रभारी (भिलाई इस्पात संयंत्र) श्री चित्त रंजन महापात्र ने किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) श्री ए.के. चक्रवर्ती, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) श्री प्रवीण निगम, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री पवन कुमार, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) श्री पी.के. सरकार, कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी, कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक (खदान) श्री आर.बी. गहरवार, व मुख्य महाप्रबंधकों सहित सेल निगमित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, एवं संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर की 100 से अधिक विक्रेता कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

अपने संबोधन में निदेशक प्रभारी (भिलाई इस्पात संयंत्र) श्री चित्त रंजन महापात्र ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2030-31 तक देश की इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अनुरूप देश के प्रमुख इस्पात उत्पादक व्यापक विस्तार पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेल ने वर्ष 2030 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 35 मिलियन टन तक

बढ़ाने की परिकल्पना की है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता को 6.8 एमटीपीए से बढ़ाकर 10.2 एमटीपीए करना एक महत्वपूर्ण घटक है।

उन्होंने कहा कि भारत की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था से इस्पात की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही हैं, जिससे इस्पात उद्योग के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रणालियों तथा सुरक्षित कार्य-पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्ववर्ती विस्तार परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी हितधारकों से चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करते हुए आगामी परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागियों से सम्मेलन के दौरान उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचारी कार्यान्वयन पद्धतियों, लॉजिस्टिक्स अनुकूलन तथा सहयोगात्मक समाधानों पर सार्थक विचार-विमर्श करने का भी आग्रह किया, जिससे परियोजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) श्री पी.के. सरकार ने 'समन्वय-2026' की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीएसपी की प्रस्तावित क्षमता वृद्धि केवल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से ही संभव नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सभी हितधारकों के मध्य निर्बाध समन्वय भी आवश्यक है। उन्होंने उपलब्ध सर्वोत्तम संसाधनों, सेवाओं एवं विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर बल देते हुए विक्रेताओं और सहयोगी संस्थाओं से इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। श्री सरकार ने प्रतिभागियों से इस मंच का उपयोग सीखने, अनुभव साझा करने तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए करने का आग्रह किया, ताकि विस्तार परियोजना के लिए एक सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार की जा सके। उद्घाटन सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक (परियोजनाएं) श्री अभिषेक श्रीवास्तव एवं सहायक महाप्रबंधक (परियोजनाएं) सुश्री जया तिवारी ने किया।

बीएसपी की विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी, लॉजिस्टिक एवं रणनीतिक समन्वय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में छह प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इनमें 3.44 एमटीपीए कच्चे इस्पात क्षमता विस्तार के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख तकनीकी सुविधाएं, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण एवं कमीशनिंग गतिविधियों को समाहित करने वाली समग्र परियोजना कार्ययोजना, बहु-विषयक विक्रेताओं के मध्य सहयोगात्मक सहभागिता सत्र, मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन, आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक्स एकीकरण तथा परियोजना नेतृत्व एवं विषय विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष तकनीकी संवाद शामिल हैं।

अमलेश्वर में अवैध होर्डिंग्स का जाल, कार्रवाई के अभाव में बढ़ रहा दुर्घटना का खतरा

अमलेश्वर। नगर पालिका परिषद अमलेश्वर क्षेत्र में लगातार अवैध होर्डिंग लगाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप है कि इस संबंध में कार्रवाई करने से पालिका प्रशासन बचता नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होर्डिंग्स के टेंडर की प्रक्रिया पिछले लगभग एक वर्ष से लंबित है, जिसके चलते नगर पालिका को राजस्व हानि उठानी पड़ रही है और अवैध होर्डिंग लगाने वालों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर, बिल्डिंग ठेकेदार एवं विभिन्न व्यापारी अपनी-अपनी प्रचार सामग्री और होर्डिंग्स बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों के किनारे लगा रहे हैं। जहां जगह मिल रही है, वहां होर्डिंग्स स्थापित या चिपकाई जा रही हैं। इस स्थिति को लेकर नगर पालिका के राजस्व विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था होर्डिंग कैसे लगा सकती है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही

है। चिंता की बात यह भी है कि कई होर्डिंग्स तेज हवा और तूफान के दौरान उखड़ चुकी हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ही एक मामला मगरघटा क्षेत्र में सामने आया है। मल्टी स्पोर्ट सिटी के पास स्थित एक बड़ा होर्डिंग पिछले सप्ताह आए तेज हवा-तूफान में उखड़कर सड़क किनारे आ गिरा और सफेद लाइन तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसे नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में नगर पालिका के राजस्व विभाग के सभापति राजू सोनकर ने बताया कि वर्तमान में होर्डिंग्स से किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसके कारण नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है और लोग मनमाने ढंग से अवैध होर्डिंग्स लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क किनारे गिरे हुए होर्डिंग्स दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसके बावजूद हफ्ते भर से पड़े होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं होना चिंता का विषय है। इस पूरे मामले को लेकर नगरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है तथा प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की जा रही है।

राजहरा माइंस हॉस्पिटल में 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफल आयोजन, 650 से अधिक मरीज हुए लाभान्वित

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा माइंस हॉस्पिटल में दिनांक 01 जून 2026 को 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य राजहरा एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञताओं के चिकित्सकों की बहु-विषयक टीम द्वारा व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

चिकित्सा शिविर के दौरान लगभग 650 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श किया गया। लाभार्थियों को हृदय रोग, मेडिसिन, अस्थि रोग, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), त्वचा रोग, दंत चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा तथा दर्द प्रबंधन सहित विभिन्न

विषयों में विशेषज्ञ परामर्श एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर के दौरान 25 इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए गए तथा 6 मरीजों को प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

इस मेगा मेडिकल कैंप में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष (सर्जिकल ट्रॉमा) डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. चंदन दास, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद बिनयके, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. इमैनुअल मैसी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कौशिक किशोर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभदीप कौर, दंत शल्य चिकित्सक डॉ. वनिता शर्मा, सामान्य शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. धीरज शर्मा, दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ. शिखा अग्रवाल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक अग्रवाल, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शिवप्पा तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आरती जैन शामिल थीं। इसके अतिरिक्त डीएनबी रेजिडेंट्स डॉ. शुभम (ऑर्थोपेडिक्स), डॉ. शालिनी (प्रसूति एवं स्त्री रोग), डॉ. श्रेयस (नेत्र रोग) एवं डॉ. पूर्णिमा (मेडिसिन), सहायक प्रबंधक श्रीमती देवकी साहू, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट श्री कल्लोल मैती तथा फिजियोथेरेपिस्ट श्री दिग्विजय ने भी शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों, डीएनबी रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल कर्मियों एवं सहयोगी स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के निदान, उपचार एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (आईओसी राजहरा) श्री आर. बी. गहरवार, सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन-आईओसी राजहरा) श्री तुषार राय चौधरी तथा उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही चिकित्सा, नर्सिंग, प्रशासनिक एवं सहायक टीमों के समन्वित प्रयासों से यह शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

राजहरा माइंस हॉस्पिटल द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे ऐसे मेगा मेडिकल कैंप क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सुशासन तिहार के दौरान शिविर में जनता से अशिष्ट व्यवहार करने पर त्वरित कार्यवाही

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने और आम जनता से अशिष्ट व्यवहार (कदाचरण) करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर अभिजीत सिंह के प्रस्ताव और शासन द्वारा आयोजित 'सुशासन तिहार' के तहत ग्राम थनौद के जन समस्या निवारण शिविर में सीईओ पाण्डेय द्वारा जनता से की गई बदसलूकी के वीडियो क्लिप के आधार पर की गई है। इस संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का सीईओ द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)

कार्यालय आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)

नियम, 1966 के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहना, कर्तव्यपरायण रहना और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना अनिवार्य है जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो, तथा नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा, ऐसा उपबंधित है।

दुर्ग में 48 नए पुलिस अफसरों को मिला गुरुमंत्र, साइबर अपराध पर रहेगा फोकस

दुर्ग। पुलिस की नई फौज अब मैदान में उतरने को तैयार है और उन्हें पहली ही ब्रीफिंग में साफसंदेश दे दिया गया है कि वर्दी का असली सम्मान जनता के विश्वास से मिलता है। इसी सोच के साथ सोमवार 1 जून 2026 को दुर्ग में 47 परिविक्षाधीन उपनिरीक्षकों और 1 सूबेदार की विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नवप्रशिक्षु अधिकारियों को पुलिसिंग की बारीकियों से रूबरू कराया।

ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, जनता के प्रति मधुर व्यवहार और निरंतर सीखने की भावना ही एक सफल पुलिस अधिकारी की पहचान है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को समझाया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि आम लोगों का भरोसा जीतना भी है। इस दौरान दुर्ग जिले की भौगोलिक स्थिति, अपराध के बदलते स्वरूप, संवेदनशील क्षेत्रों और यातायात व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई ताकि अधिकारी जमीनी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

बैठक में साइबर अपराधों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को बताया गया कि बदलते दौर में साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इस पर प्रभावी निगरानी तथा त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु अधिकारियों को जिले में होने वाले विभिन्न अपराधों, वीआईपी ड्यूटी और कानून-व्यवस्था प्रबंधन की महत्वपूर्ण बारीकियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस अधीक्षक लाइन सी.पी. तिवारी और रक्षित निरीक्षक नीलकंठ वर्मा भी मौजूद रहे। बहरहाल, दुर्ग पुलिस ने अपने नए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बेहतर पुलिसिंग की शुरुआत जनता के प्रति संवेदनशीलता, अनुशासन और सतत सीखने की भावना से ही होती है।

आयुक्त ने स्थानीय पार्षद के साथ स्मृति नगर वार्ड का किया निरीक्षण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत साफ -सफाई, अवैध प्लाटिंग, नाला सफाई सहित अन्य कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किये। उपस्थित अधिकारियों को सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने निर्देशित किये हैं। निगम आयुक्त, पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल के उपस्थिति में वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर के वार्डों का जायजा लिये। वार्ड में साफ -सफाई व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किये और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने कहा गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिले। बरसात में अधिक वर्षा होने से निचली जगहो पर जलभराव हो जाता है, जिससे नागरिको को परेशानी होती है, ऐसे डूबान क्षेत्र के समस्या को सुधार कराने निर्देशित किये हैं। वार्ड में ही कुछ अवैध प्लाटिंग कर नागरिको को बेच दिया गया है। खरीदीकर्ताओं द्वारा निर्माण भी किया जा रहा है, उन अवैध प्लाटिंगकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। समीपस्थ बरसात से पूर्व बड़े नाला की सफाई कराने कहा गया है, जिससे बरसात का पानी न रूके। स्मृति नगर में कुछ माह पूर्व नाली निर्माण किया गया है, जो अव्यवस्थित हो गया है संबंधित के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने कहा गया है। आनंद नगर में नया नाली निर्माण कराने के आदेश दिया गया है, जिससे नागरिको को सुविधा मिले। आयुक्त ने सड़को का जायजा लिये, कुछ स्थल में सड़क संधारण की आवश्यकता है, संधारण कराने निर्देशित किया गया है। स्मृति नगर में स्थानीय नागरिको द्वारा अपने घरो के सामने नाली के उपर ढलाई कर वाहन पार्किंग के लिए संरचना बनाया गया है, जिससे नालियों की सफाई में रूकावट हो रही है। उन सभी नालियों के उपर से ढलाई हटाकर सफाई कराने कहा गया है। आयुक्त ने पुष्पक नगर स्थित मार्केट का अवलोकन किये और नाली, सड़क की सफाई कराने कहा गया है साथ ही पेवर ब्लाक को व्यवस्थित करने निर्देशित किये हैं।

कलेक्टर ने की जिले में प्रगतिरत सात समूह जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा

ओदरागहन समूह जलप्रदाय योजना से शीघ्र शुरू होगी जलापूर्ति

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर सिंह ने जिले में संचालित विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में प्रगतिरत 07 समूह जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ओदरागहन समूह जलप्रदाय योजना से शीघ्र जलापूर्ति प्रारंभ की जाएगी। वहीं अंजोरा ढाबा एवं मोतिमपुर समूह योजनाओं में विद्युत कनेक्शन से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत निरस्त किए गए अनुबंधों के मामलों में शीघ्र नई निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन एजेंसियों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया है, उनके संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने के को कहा। कलेक्टर ने अमलेश्वर समूह योजना में शामिल चार ग्राम- अमलेश्वर, मगरघटा, खुड़मुड़ी एवं भोथली को संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने हेतु संयुक्त निरीक्षण के बाद आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जिन ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनका संचालन एवं संधारण संबंधित पंचायतों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत को नल जल मित्रों का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मिशन संचालक, जल जीवन मिशन से प्राप्त निर्देशानुसार 'लोक जल उत्सव' वार्षिक कैलेंडर को जिला वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करते हुए ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिले में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, खिलाड़ियों को बांटे गए प्रमाण पत्र

दुर्ग। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला-दुर्ग द्वारा आयोजित वर्ष 2026-27 के 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का विधिवत समापन हो गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्रशिक्षण शिविर 11 मई 2026 से 31 मई 2026 तक जिले के पृथक-पृथक 17 खेल मैदानों में संचालित किया गया था, जिसमें बालक-बालिका खिलाड़ियों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी, नेटबॉल, ताईक्वांडो एवं कुश्ती जैसे विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर के अंतर्गत फुटबॉल खेल का समापन के.डी. पब्लिक स्कूल बोरसी के खेल

मैदान में आयोजित किया गया, जहाँ समापन समारोह के मुख्य अतिथि भूषण साहू (संचालक, के.डी. पब्लिक स्कूल बोरसी), अलबियुस एक्का (सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, जिला-दुर्ग) तथा भूपेन्द्र कुमार हिरवानी (फुटबॉल प्रशिक्षक) विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह के दौरान ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभावान बालक एवं बालिका खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा सहायक संचालक अलबियुस एक्का ने खेल की बारीकियां सीखने वाले इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

पाटन उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, उर्वशी शैलेश साहू विजयी

पाटन। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत जनपद क्षेत्र क्रमांक 04 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उर्वशी शैलेश साहू ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भाजपा द्वारा दिए गए कांग्रेस मुक्त पाटन के नारे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उर्वशी शैलेश साहू को विजय दिलाई। पाटन क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मैं हूं भूपेश का नारा पूरी तरह सफल साबित हुआ। इस ऐतिहासिक जीत में पुर्व मुख्य मंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पूर्व जिला पंचायत सभापति चुनाव प्रभारी मोनू साहू के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं युवा नेता चैतन्य बघेल, कांग्रेस नेता आशीष वर्मा तथा जिला अध्यक्ष राकेश साहू के सफल मार्गदर्शन और रणनीति से कांग्रेस को यह बड़ी जीत हासिल हुई। उर्वशी साहू के पक्ष में क्षेत्र की जनता का सहानुभूति समर्थन एक बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आया। कांग्रेस की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि पाटन में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं और जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ कायम है।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995